[Shri Syed Shahabuddin]

to amend the Indian Telegraph Act, 1885.

The questions was put and the motion wa^s adopted.

SHRI SYED SHAHABUDDIN: Sir, I introduce the Bill.

THE PRESS (PLANNING AND FREEDOM) BILL,—contd.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): Last time, Mr. Ram Bhagat Paswan was on his legs. Is he there? ...No. *(Interruptions)* Then, Mr. Sukul, Are you going to speak on this Bill... (Interruptions)

आपकी पार्टी का आदमी नहीं है । आप बोलना चाहते हैं तो बोलिये ।

श्री पी० एन० सुकुल (उत्तर प्रदेश) : वाइस चेयरमैन साहब, हमारे मित्र श्री शिव चन्द्र झा जी इस विधेयक को लाये हैं । प्रेस (आयोजन तथा स्वतंत्रता) विधेयक, 1978 इसमें लिखा है । यह बहुत पुराना विधेयक है । मैं अभी इस विधेयक को पढ़ रहा था और मैंने इस विषय पर झा जी से भी चर्चा की थी मेरी समझ में नहीं आया कि झा साहब यह विधेयक यहां पर क्यों लाये ? मैं झा साहब का बड़ा आदर करता हूं और मुझे उनकी विद्वता में कभी भी सन्देह नहीं रहा । वे विदेश के पढ़े हुए हैं । उन्होंने एम० जे० किया हुआ है और जनरेलिज्म में काफी उपलब्धि प्राप्त की है । लेकिन जिस प्रकार का बिल वे यहां पर लाये हैं उससे तो मुझे बड़ी घोर निराशा हुई है ।

एक ओर तो झा साहब प्रेस की स्वतंत्रता की दुहाई देते हैं और इनका कहना है कि भारतवर्ष में प्रेस की स्वतंत्रता बिलकुल नहीं है, समाप्त हो गई है और जब पिछली बार वे बोल रहे थे तो इस सदन में उन्होंने तमाम अखबारों के नाम गिनाये थे । स्टेट्समैन का नाम भी गिना दिया था और कहा था कि पहले यह अंग्रेजी साम्राज्यवाद से प्रभावित था और अब अमेरिकी साम्राज्यवाद से प्रभावित है । उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान में कोई भी फ्रीडम आफ प्रेस नहीं हैं । हिन्दुस्तान में कोई भी फ्रीडम आफ प्रेस झा साहब को दिखाई नहीं पड़ रही है क्योंकि अधिकांश यहां के जो अखबार हैं वे सब मिल-मालिकों के कब्जे में हैं । पार्टियों के जो अखबार या पीरिओडिकल्स हैं उनकी भी चर्चा झा साहब ने की है । सबसे ज्यादा मजेदार बात जो उन्होंने कही वह यह लगी कि झा साहब ने कहा कि जनता पार्टी का जो वीकली बम्बई से निकलता है उसको कोई छूता तक नहीं है । उन्होंने कहा कि सी०पी०आई० (एम) का अखबार लोक बिहार जो निकलता है उसको कोई पढ़ता नहीं है । यह दुर्दशा है हमारी। राजनीतिक पार्टियों की। मोस्ट इम्पार्टेन्ट राजनैतिक पार्टियां हैं, चाहे जनता पार्टी हो, सी पी०आई० (एम) हो, जो नाम उन्होंने गिनाये हैं । एक ओर इन राजनैतिक पार्टियों द्वारा निकाले जाने वाले जो अखबार हैं उनको कोई पढ़ता नहीं, उनको कोई छूता नहीं और दूसरा ओर झा साहब यह बिल लाये हैं जिसके द्वारा यह चाहते हैं कि राजनैतिक पार्टियां अखबार निकालें । मेरी समझ में नहीं आया कि कैसे और क्या सोचकर झा साहब इस बिल को लाने पर मजबूर हो गये । मेरी यह बात समझ में आने वाली नहीं है । आपका कहना है कि प्राइवेट प्रेस को खत्म कर दीजिये हिन्दुस्तान से और आप प्रैस को इंडस्ट्री मानने के लिये भी तैयार नहीं है । ये कहते हैं कि प्रेस इंडस्ट्री नहीं होनी चाहिए । क्योंकि यह इंडस्ट्री है और इसीलिये इंडस्ट्रियलिस्ट इसको रन करते हैं, मिलिनियर उसको

रन करते हैं। हो सकता है उल्टी बात भी हो, रन करते-करते कोई मिलिनियर बन गया हो, पैसा इकट्ठा कर लिया हो। दोनों बातें है। तो ये प्राइवेट प्रेस को खत्म करना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि 'नवभारत टाइम्स' 'स्टेट्समैन' ये जो सब अखबार हैं इनकी गवर्नमेंट टेक-ओवर करे इनका प्रस्ताव है कि जो प्राइवेट प्रेस है उसको खत्म करके उसका नेशनलाइजेशन कर दिया जाये। झा साहब ने अपने उस दिन के भाषण में कहा कि मैंने जो नेशनलाइजेशन शब्द का इस्तेमाल किया, कहा, मेरा मतलब वह नहीं है जो आप समझते हैं। मैंने इनका पूरा भाषण उस दिन का पढ़ा है नेशनलाइजेशन भी आप कराना चाहते हैं। एक और आप यह भी कह रहे हैं कि श्रीलंका में श्रीमती भंडारनायके ने प्रेस का नेशनलाइजेशन कराया तो उसके करने से उनकी पार्टी चली गई, सरकार से खत्म हो गई और दूसरी और आप चाहते है कि प्राइवेट प्रेस को खत्म करके सब के ऊपर सरकार का कन्ट्रोल हो जाये। तो यह जो आपने कहा है मेरी समझ में नहीं आता कि यह कौन सा तर्क है, कौन सा लाजिक दे रहेहैं। पता नहीं कहां बैठकर उन्होंने सोचा है। जो आदमी बहुत ज्यादा बोलता है, बहुत ज्यादा सोचता है तो उसका यही हश्र होता है। कभी-कभी बहुत ज्यादा सोचने में भी बहुत सी गड़बड़ियां पैदा हो जाती हैं। आप यह चाहते हैं कि सिर्फ दो तरह का नियंत्रण, कन्ट्रोल हो, दो तरह के अखबार हों। एक तो प्लान्ड प्रेस और दूसरा पोलिटिकल प्रेस। यह झा साहब के बिल का लब्बोलुबाब है, प्लान्ड प्रेस और पोलिटिकल प्रेस। आपका सुझाव है कि एक प्रस बोर्ड बने, प्लानिंग कमीशन के तहत में और वह प्रस बोर्ड सारे अखबारों पर, सारे देश के समाचार-पत्रों पर नियंत्रण रखे, वह इन्हें देखे और उस प्लान्ड प्रेस को वह चलाये। जो सरकारी कर्मचारी होंगे वे इस प्लान्ड प्रेस को देखेंगे और इसके बारे में उन्होंने कहा कि प्लान्ड प्रेस, हिन्दी में जो आपने इसके लिये शब्द दिया है, मुझे उस पर आपत्ति है। उन्होंने लिखा है आयोजित प्रेस, यह हिन्दी में दिया हुआ है। हिन्दी इसकी ठीक नहीं हुई। प्लान्ड प्रेस का मतलब है नियोजित प्रेस।

श्री शिव चन्द्र झा (बिहार) : मैंने हिन्दी नहीं की है।

श्री पी. एन. सुकुल : बिल आपका है, आपके नाम से बिल आया है। इसको नियोजित प्रेस होना चाहिए, आयोजित प्रेस नहीं होना चाहिए। आपने नियोजित प्रेस को आयोजित प्रेस लिखा। प्रेस बोर्ड द्वारा यह चलना चाहिए यह आपने कहा है। आपने कहा है कि यह नियोजित प्रेस जो होगा वह क्या-क्या करेगा। पहला, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों की प्रशासन योजनाओं और परियोजनाओं पर ध्यान सकेंद्रित करेगा। दूसरा, निष्पक्षता से राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय समाचार प्रस्तुत करेगा और तीसरा, जनसाधारण के लिये संपादक के नाम पत्र स्तम्भ और लेखों और पुस्तकों की समीक्षाओं के लिये अधिक स्थान आबंटित करेगा। यह हमारी प्लान्ड प्रेस का कर्त्तव्य इन्होंने बताया कि वह जो है वह केवल राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय समाचार देगा और सरकार की योजनाओं के बारे में आपको जानकारी देगा और जो छुटपुट स्तम्भ जैसे संपादक के नाम पत्र रहते है, वह करेगा। पोलिटिकल कमेंटरी वह नहीं करेगा, पोलिटिकल टिप्पणी वह नहीं करेगा। राजनीति की बात नहीं करेगा, राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय समाचार वह जरूर देगा लेकिन राजनीतिक समाचार इसके मायने वह नहीं देगा क्योंकि राजनीति के लिए आपने बताया है कि पोलिटिकल प्रेस राजनीतिक पार्टियों के जो पत्र आज चालू हैं और राजनीतिक पार्टियां जैसे कि मैंने शुरु में कहा आज हर राजनीतिक पार्टी अपना अखबार निकाल रही है चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वह मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे वह कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया हो और चाहे

[श्री शिवचन्द झा]

वह जनता पार्टी हो। कांग्रेस पार्टी का अखबार नेशनल हैराल्ड है ही। तमाम जितनी पार्टियां हैं सब आज अखबार निकाल रही हैं, वे काम जो आज आप कराना चाहते हैं। एक ओर आप कहते हैं जो निकाल रहे हैं उन्हें कोई पढ़ता नहीं, छूता तक नहीं, देखता नहीं और फिर भी आप कहते हैं नहीं यह व्यवस्था होनी चाहिये। वे आगे भी निकालें। तो यह दलील वास्तव में बड़ी निराशाजनक है। कम से कम शिव चन्द्र भा जी जैसे अनुभवी, तपे हुए, अमरीका में पढ़े हुए जो हमारे माननीय सदस्य हैं कम से कम उनकी ओर से ऐसी चीज की अपेक्षा हम ने नहीं की थी। फर्क क्या है। फर्क हमारी समझ में सिर्फ यह आया कि झा साहब चाहते हैं कि राजनीतिक पार्टियों को सरकार अखबारों के लिए पांच लाख रूपया सालाना दे जिसकी व्यवस्था आपने की है। हर पार्टी को भारत सरकार पांच लाख रुपया दे ताकि उनका आखबार निकले और उस अखबार में आप भारत सरकार को उस पार्टी की जिसकी सरकार है आप गाली दें, बुरा भला कहें। हम आपको रुपया दें कि आप हमारी सरकार को गाली दें।

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी (आंध्र प्रदेश) : जब हम पावर में रहेंगे...

श्री पी एन सुकुल : आप हम से रुपया ले कर हमारे ऊपर पत्थर मारो।

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : जब हमारी सरकार बनेगी

श्री शिव चन्द्र झा : सुकुल जी जरा...

श्री पी० एन० सुकुल : झा साहब मैं बिलकुल खामोश रहा जब आप बोल रहेथे तो आप भी मेरी बात सुनिये। I am younger than you and I can shout much better. पांच लाख रुपये का सवाल है, ठीक है, हम तो नहीं मांग रहे हैं। आप कहते हैं हम तो नहीं कहते कि कांग्रेस पार्टी को अखबार निकालने के लिए सरकार दे। क्यों दे ?

श्री रामेश्वर सिंह (उत्तर प्रदेश) : कांग्रेस पार्टी को तो पांच करोड़ रुपया मिल रहा है **(व्यवधान)**

श्री पी० एन० सुकुल : यह तो आपके चौधरी साहब ने भी एक अखबार निकालने की योजना बनाई थी **(व्यवधान)** पूरी शुगर लाबी आपकी है फिर क्यों नहीं निकाला, जो अखबार निकालना हो निकाल लेना। जैसे आप कहते हैं। कोई भी उद्योग-पति जिसके पास दो, चार, दस लाख रुपया है वह एक अच्छा अखबार निकाल सकता है और जिसके पास पचास हजार रुपया है वह भी एक सीमित न्यूज पेपर निकाल सकता है जैसे कि आजकल तमाम जिलों में एक दो पन्ने के अखबार आज निकल रहे है। लेकिन इस बिल की क्या आवश्यकता थी। आज जो काम यहां हो रहा है झा साहब कहते हैं कि आज फ्रीडम आफ प्रेस इंग्लैंड में भी नहीं है। आपने अपने भाषण में कहा था उस दिन एनुरिन बेविन की बात की थी। फ्रीडम आफ प्रेस क्या कर रहा है। झा साहब का कहना है कि अमरीका में आज फ्रीडम आफ प्रेस नहीं है। इन दो देशों के नाम आपने लिए थे जहां तक सोवियत रूस, चाइना या जो दूसरे सोशलिस्ट कन्ट्रीज हैं उनके बारे में मैं कह सकता हूं कि वहां भी फ्रीडम आफ प्रेस नहीं है। आप किस प्रकार की फ्रीडम आफ प्रेस की कल्पना करते हैं वह भी कैसे भौंडे ढंग से की है। सरकार के खर्च के ऊपर फ्रीडम आफ प्रेस। प्राइवेट ईन्ट्रप्रानर्स को खत्म करके उसका सरकारीकरण और सरकारीकरण आप कराना चाहते हैं सिर्फ पांच लाख रुपया लेने के लिए। मैं समझता हूं आज जो लोग अखबार निकाल रहे हैं बड़े-बड़े जैसे कि आपने कहा 75 अखबार बड़े हैं, 32 घराने हैं जो निकाल रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनमें भी कोई भी यह नहीं

कहेगा कि ठीक है । सरकार से एडवरटिजमेंट सब लेते हैं । सरकार उनको देती है, मदद करती है । जो चीजें हैं सब के लिए सामान रूप से सरकार कर रही है । उस दिन फ्रीडम आफ प्रेस की बात करते करते आप आकाशवाणी और दूरदर्शन को क्रिटिसाईज करने लगे और सबसे तो अखरने वाली बात यह थी कि आपने जो हमारे इन्फारमेशन एण्ड ब्राडकास्टिंग मिनिस्टर श्री माठे साहब हैं उनको कहा कि उनको फ्रीडम आफ प्रेस मालूम ही नहीं है । The Minister does not know freedom of press. वे तो बन गए मंत्री, सब मंत्री बन जाते है, वे भी बन गए । पर मेरा दावा यह है कि शिव चन्द्र झा जी फ्रीडम आफ प्रेस मालूम नहीं है ।

श्रीमती सरोज खापर्डे (महाराष्ट्र) : आपका दावा सही है ।

श्री पी० एन० सुकुल : जो यह बिल लाये हैं, गैर जरूरी बिल निहायत अहमकाना और बचकाना जिसके ऊपर कि हम आज अपना वक्त बरबाद कर रहे हैं ऐसा बिल देख करके तो उपसभाध्यक्ष महोदय, हमें बड़ी हंसी आई और आप कहते क्या है ? आपका कहना है जहां तक इसके आब्जेक्ट्स और रीजन्स इसमें दिये हुए हैं, उसमें अगर आपने पढ़ा तो वह बहुत ही शानदार बात है, आप स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एंड रीजन्स में कहते हैं Freedom of the press is the bulwark of liberty. With growth of industrialisation, the press has become more an enterprise and business than an ideal free press.

बिल्कुल सहीIt has become an enterprise and bus iness than an ideal free press

इतनी बड़ी इंडस्ट्री है आज यह इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में कवर्ड है, फैक्ट्री एक्ट में कवर्ड है, वहां के स्टाफ को, इम्प्लायीज को इन एक्टों के मातहत तमाम तरह तरह की सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, दी जा रही हैं । आपका यह कहना है कि इंडस्ट्रलाईजेशन की वजह से जो यह इन्टरप्राईज और बिजिनेस बन गया है वह गलत है । बिजिनेस तो वह है ही गवर्नमेंट का प्रेस हो सकता है बिजिनेस न हो । क्योंकि लोकतंत्र के हित में जन सेवा की दृष्टि से तमाम समाचार, तमाम दूसरी बातें हमें जनता तक पहुंचानी हैं, वह गवर्नमेंट का धर्म है, कर्तव्य है, वह गवर्नमेंट करती है, करेगी इसलिए तमाम पीरियाडिकल, न्यूजपेपर्स निकल रहे हैं । तो गवर्नमेंट का जो प्रेस है उसका प्रोफिटीयरिंग मौटिव नहीं भी हो सकता है लेकिन जो प्राईवेट प्रेस आज है, कायदे से जिसको फ्री प्रेस कहा जाना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान के अखबारों को जितनी फ्रीडम मिली हुई है हमारे प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति से लेकर, हर एक को आलोचना करने को और तमाम ऊल-जलूल बातें कहने को, यह फ्रीडम शायद हो और कहीं आपको मिलेगी और इसके बावजूद झा साहब हमारे समझते हैं कि नहीं सारे अखबार बंद हो जाने चाहिए, चाहे वह 'हिंदुस्तान टाईम्स' हो, चाहे 'नवभारत टाईम्स' हो, या 'स्टेट्समैन' हो और उनको हमारी प्लानिंग कमीशन टेकओवर कर ले या प्लानिंग बोर्ड उसके मातहत जो काम करेगा, वह उसको चलाये ।

आप दरअसल प्लान्ड प्रेस की बात करके आज जो प्राईवेट प्रेस है—क्योंकि पोलिटिकल प्रेस तो मौजूद है, कोई नया पोलिटिकल प्रेस लाने की आज जरूरत नहीं है, जिसकी व्यवस्था आप इसमें कर रहे हैं, आपने उसका चर्चा की है । हर पार्टी का, जैसा मैंने कहा प्रेस मौजूद है, हर पार्टी निकाल रही है और कम से कम उनके आपने जो मेम्बर्स हैं सदस्य हैं वे उनको लेने भी होंगे और वे अगर उनको लेते हैं, अब अगर कोई पार्टी है और उस पार्टी के अपने सदस्य उस अखबार को नहीं खरीदते हैं जिनके लिए कि यह निलकता है, जैसा कि आपने खुद एडमिट किया कि कोई पढ़ता नहीं, छूता नहीं, तो आप उ पोलिटिकल पार्टी के लोग, उसके सदस्य उस

[श्री पी० एस० सुकुल]

अखबार के सबस्क्राईबर नहीं बनेंगे वे उसका उसका चंदा नहीं देंगे, (**समय की घंटी**) लेकिन गवर्नमेंट से कहेंगे कि यह पांच लाख रुपया आपको दे ताकि आप छापो और वह रद्दी के भाव बिके तो यह आपकी जो नयी खोज है, जो दूरदर्शिता है, क्षमा कीजिएगा सभापति महोदय, मेरी समझ में, कि किस प्रकार से सिर्फ पांच लाख रुपये दिलाने के लिए ऐसी पार्टियों को जिनके कि अखबार चलते नहीं हों, आज एक बिल लाया जा रहा और वह भी to stregthen democracy and to ensure freedom of the press. आप

3.00 P.M.

डेमोक्रेसी को मजबूत बनायेंगे सारे वर्तमान का अखबारों का स्वामित्व समाप्त करके, उनका नेशनलाइजेशन करके । जब सरकार उनको ग्रांट देगी, सरकारका ही प्लैनिंग बोर्ड उन पर नियंत्रण करेगा, तो आप इसकी कल्पना कर सकते है कि क्या स्थिति होगी ?

आज बिना सरकार से ग्रांट के जो अखबार रहे हैं, हमारा जूट प्रेस है, जैसे उस दिन चर्चा हुई, आज उन्हें जरूरत नहीं है कि सरकार से वह पांच लाख रुपया ले । वह निकाल रहे हैं और जो चाहते हैं, वह छाप रहे है—

They are exercising their freedom to their own satisfaction. May not be to our satisfaction or to the satisfaction of the people. But at least, to their own satisfaction, they are doing it.

लेकिन आप जिसको जरूरत नहीं भी है, जो आज अपनी स्वतंत्रता से, अपने भावों को, अपने विचारों को, अपनी थीसिस को, अपने दर्शन को जनता तक या अपने सदस्यों तक दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि उसको बंद कर कर दिया जाए, एक प्रेस बोर्ड बना दिया जाए और उस बोर्ड में अर्थ-शास्त्री रख दिये जाएं और कुछ पुराने जर्नलिस्ट रख दिये जाएं और वह अर्थ-शास्त्री और वह जर्नलिस्ट जो होंगे, वह मिल करके सारी फ्रीडम इन्योर कर देंगे, ऐसा चलेगा । सरकारी खर्चे पर कोई भी चीज जब चलेगी, सरकार के अनुदान पर चलेगी, आप बतलाइयेगा कि जो आपका यह बेसिक कनसैप्शन है, तो वहां फ्रीडम कहां रहां

Where is that freedom? If all the press run by the Government themselves, if they are financed by the Government themselves, where is the freedom you are talking of?

झा सहाब, यह जो आपका बिल है, मैं समझता हूं कि यह रद्दी की टोकरी में फैंकने के लिए सब से बढ़िया कागज है । इससे बढ़िया स्थान इस बिल के लिए हमारी समझ में और कोई नहीं हो सकता और इसीलिए मैं बिलकुल अपने अंतरतम से इसका विरोध करता हूं और शिव चन्द्रझा साहब को यह बताना चाहता हूं कि उनका, जैसे कि हमारे धाबे साहब ने उस दिन कहा था बोलते हुए कि, रजिस्ट्रार आफ न्यूजपेपर्ज आफ इंडिया की जो चौबीसवीं रिपोर्ट है जिसमें कहा जा रहा है कि —

—Newspapers are on the increase every year.

अखबारों की संख्या हमारे यहां बढ़ती चली जा रही है । संख्या बढ़ नहीं सकती अगर उसकी इकनामिक्स ठीक न हो, अगर उनको प्रापर रिटर्न न मिले, तो संख्या कैसे बढ़ेगी ? पढ़ने वाले न हों, तो संख्या कैसे बढ़ेगी ? अगर लोगों को पढ़ने की इच्छा न हो, आस्था न हो, जरूरत न हो, तो अखबार कैसे निकलेगा ?

तो आज जो हो रहा है, जो आज की परिस्थिति है, जिस प्रकार की व्यवस्था है, वह सर्वोत्तम है और मैं नहीं चाहता हूं कि झा ज के कथनानुसार सारे प्रेस जो आज हैं, वह समाप्त कर दिये जाएं और उनका सरकारी-करण हो जाए ।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ झा साहब के इस विचाराधीन विधेयक का पुरजोर विरोध करता हूं ।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (बिहार): उपसभाध्यक्ष जी, यह जो विधेयक अभी सदन के सामने विचाराधीन है, इस विधेयक के मोटे-मोटे तौर पर कुछ बिंदुओं पर चर्चा की

गई है, कुछ बातें हैं मोटे-मोटे तौर पर और उसमें बोर्ड के गठन से लेकर दस हजार से ज्यादा सर्कुलेशन वाला हो, तो उसको सरकार अपने हाथ में ले ले, समाचार के लिये जो नियोजित प्रेस हो, उसमें किस-किस तरह के समाचार के लिए कितना स्थान उसमें होना चाहिए, सरकार की पार्टी के द्वारा समाचार-पत्र निकलवाने के, यह सब जो न्यूज सर्विस एजेंसी है, वह प्रेस बोर्ड के अंदर होनी चाहिए और प्रेस बोर्ड पर योजना आयोग का नियंत्रण होना चाहिए, तो यह सब जो श्री शिव चन्द्र झा जी इस बिल में लिख रहे हैं, यह उस सरकार के लिए लागू हो सकता है जिस देश की सरकार बिलकुल ही लोकतंत्र और जनतंत्र के लिए काम करने वाली हो। जहां ऐसी बात न हों ही, जहां सरकार द्वारा नामिनेशन करने का सवाल हो और जहा लोकतंत्र और ज तंत्र में विश्वास नहीं है वहां इनकी क्राइटेरिया के मुताबिक प्रेस बोर्ड को चेयरमैन सरकार नामिनेट करेगी तो किसी आदमी को जिसका प्रेस बोर्ड क्या है नहीं मालूम उसको चेयरमैन बना दिया जाएगा जिसमें ऐसे आदमियों को मैम्बर बना दिया जायेगा जो न प्रेस के बारे में जानता है, न समाचार पत्रों के बारे में, जानता है, जो न छापाखाना देखा हो, न अखबार पढ़ता हो और अगर सरकार के जरिये नियंत्रण होगा, योजना आयोग के अन्तर्गत प्रेस बोर्ड के मैम्बरों का नामिनेशन सरकार के द्वारा दिया जायेगा तो घूम फिर कर श्री वसन्त साठे के हाथ को सोलह आना मजबूत कर देगा। श्री वसन्त साठे जिसे चाहें, किसी आदमी को पीर, बावर्ची भिस्ती, जिसको चाहे मैम्बर बना दें, जिस को चाहे चैयरमैन बना दें और यह कहें कि उनको प्रेस चलाने का पूरा-पूरा ज्ञान है। कोई पूछे कैसा ज्ञान है तो कह देंगे कि उनके पास कहीं से सार्टिफिकेट है। सरकार की बाहें लम्बी होती हैं, जिसको चाहे सरकार बना दे। इस प्रेस बोर्ड पर सरकार का नियंत्रण होगा हांलाकि श्री शिव चन्द्र झा जी की भावना दूसरी है। वह जिस भावना से इसको लाये हैं उस भावना से सरकार इसको करेगी नहीं। सरकार के हाथ में अगर इस तरह की व्यवस्था दे दी जाये तो बंदर के हाथ में तलवार देने जैसा होगा। सरकार के हाथ में इस विधेयक के जरिये ताकत देना इसके हाथ को मजबूत कर देना होगा। वह जिसे चाहे नियुक्त कर देगी। कोई अच्छा आदमी प्रेस बोर्ड में रखा नहीं जायेगा जिसको सब बातों की जानकारी है। यह तो पहली बात है।

10,000 से ज्यादा सर्कुलेशन वाले अखबार जो हैं उनको सरकार अपने हाथ में ले कर चलाये। सरकार कितनी चीजे चलाये? सरकार रेल चलाये, सरकार कोयला चलाये, सरकार पोस्ट आफिस चलाये, सरकार वाटर टैंक चलाये, सरकार बिजली चलाये। चलाते-चलाते सरकार क्या इसको भी चलाये? अपना जो उसका प्रेस है, जो सरकार का पब्लिकेशन है, वह तो पूरा चल ही नहीं पाता क्योंकि उनके पब्लिकेशन डिवीजन में साठे जी हैं। मैं जाता हूं, लौट कर चला आता हूं। उनके यहां कई ऐसी पुस्तकें हैं जो तीन-चार-पांच साल से आऊट आफ प्रिन्ट हैं। भारत सरकार का जो प्रकाशन विभाग है उसने कई राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा लिखित पुस्तकें छपवाई हैं। मैंने आग्रह किया कि एक श्री रमेश चन्द्र दत्त द्वारा लिखी पुस्तक 'इकानामिक हिस्ट्री आफ इंडिया' है जो कि सम्पूर्ण भारत में किसी भी भाषाभाषी के पढ़ने योग्य किताब है, और जो अंग्रेजी राज्य की आर्थिक व्यवस्था को पढ़ाता है तो प्रत्येक भारतीय की आंखों से आंसू की बूंद गिरने लगती हैं। मैंने कहा इस महत्वपूर्ण किताब को हिन्दुस्तान की के कई भाषाओं में अनुवाद कर दीजिये जिससे लोग उस पुरानी किताब को पढ़

[श्री हुक्म देव नारायण यादव]

सकें, जिसके मुकाबले की किताब आज नहीं मिलती है । पंडित सुन्दर लाल द्वारा लिखित भारत में अंग्रेजी राज्य और ऐसी बहुत सी किताबें हैं, महत्वपूर्ण पुस्तकें, हैं जिनको पढ़ने से लोगों को बेहद ज्ञान होता है, जो ज्ञान का सही वातावरण आदमी को उपलब्ध कराती हैं । तो उनका प्रकाशन कार्य उस विभाग से चल नहीं रहा है । फिर प्लानिन्ग विभाग के ऊपर अखबार चलाने की जिम्मेदारी दे दें तो क्या होगा नहीं होगा भगवान जाने जहां जानकारी के लिये कोई व्यवस्था नहीं है, कोई शक्ति नहीं है । हां, यदि सरकार की ऐसी कोई दिशा होती, सरकार के पास दृष्टि होती और संकल्प होता और अगर सरकार का ईरादा एक होता तो वह जिम्मेदारी देती । तब यह कुछ भी कर पाती । लेकिन देखों अब कहां जा रहे हैं । आप तो कुंयें में भांग घोटने जा रहे हैं । एक तो कुंयें में पहले से भांग भरी हुई थी अब इस तरह का कानून बना कर आप व्यर्थ में भांग छानेंगे । वैसी ही कुंये के पानी में भांग की सुगंध से नशा छा जायेगा । यह तो सरकार के हाथ में और पावर देने जा रहे हैं । यह सरकार पावर देने लायक नहीं है, अभी वर्तमान में । हां यह बात समझ में नहीं आई कि शुल्क जी बोल रहे थे कि हमें पैसा दें प्रेस चलाने के लिये तो मान लीजिये शुक्ल जी अपने टी० ए० भत्ते में से कुछ हम लोगों को देगें तो शुल्क जी की सरकार कोई स्थायी सरकार नहीं है, यह ध्यान रखिये,

"न राजा रहेगा, न रानी रहेगी
ये माटी सभी की कहानी कहेगी"

शुल्क जी की जगह पर किसी दिन हुक्मदेव नायारायण यादव भी आ जा सकते हैं अगर यही आसार होते कि आपकी ही हुकूमत और आपकी ही सरकार हमेंशा रहेगी तो हम गांव में हल चलाते, यहां पर धकमधक्का किस लिये करते । हम यह मान कर चलते हैं कि सरकार की सत्ता अपने हाथ में लेनी है । विरोधी दल का यह कर्त्तव्य है कि वह सरकार की नीतिषों की आलोचना करे और सरकार की नीतियों पर प्रहार करें । सरकार को सत्ता से हटाए और उसकी जगह सत्ता अपने हाथ में ले । यह विरोधी दल का पुनीत कर्त्तव्य है । अगर इस कर्त्तव्य से विरोधी दल हटाता है तो वह विरोधी दल नहीं है, वह हिजडों या नपुंसक की जमात हों सकती है, विरोधी दल नहीं हो सकता है आप जो कह रहे थे कि क्या तैसा देकर कोई प्रेस देश में चल सकता है, पार्टी के जरिये प्रेस चलाने के लिये जो कहा जा रहा है , इस में दृष्टीकोण यही है कि सत्ताधारी दल के पास पैसे आने के बहुत स्रोत हैं, लेकिन जो विपक्षी दल होते हैं, उसके पास पैसे के स्रोत सूखे होते हैं और होते भी हैं वह गंगा की धारा की तरह नहीं होते, बल्कि कोई-कोई छोटे-छोटे बरसाती नालों की तरह होते हैं । कहीं से कुछ झडकर आ जाये तो आ जाये । लेकिन सत्ताधारी दल के पैसे के स्रोत जो होते हैं वह गंगा की धारा जैसे अबाध गति से प्रवाहित होते हैं । इस लिये विरोधी दलों को अपने पास रखिये । कहा गया है :—

"निन्दक नियरे राखिये, आंगन कुटी छवाय,
बिन साबुन पानी बिना, निर्मल करत स्वभाव

तो यह विरोधी दलों का काम है कि वह सरकार की आलोचना करे, समालोचन करें, उसका काम केवल निन्दा करनी ही नहीं है बल्कि सरकार के द्वारा कुछ अच्छे काम भी हो जायें तो उनके बारे में सरकार को अच्छा कहना भी है । . . .

श्री पी० एन० सुकुल: अपनी पार्टी के अन्दर से चौधरी साहब को निकाल दें देते। . . . उन्होंने अपने निन्दकों को निकाला या अपने प्रशंसको को ? . . . **(व्यवधान)**

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: यह सही बात है कि अपने निन्दकों को निकालते हैं लेकिन यहां श्री नरेन्द्र सिंह जी आपके, साथ बैठे हुए हैं, वह उनके निन्दक नहीं हैं

श्री रामेश्वर सिंह : श्याम लाल यादव भी रहे हैं . . . **(व्यवधान)**

श्री पी० एन० सुकुल : चौधरी साहब कहां से गये ? . . . **(व्यवधान)**

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : आप कहां से आये । मैं कहां से आया ? आप तो सबसे बड़े निन्दक थे, हमारे साथ-हाथ में हाथ लेकर अमरजेंसी का आपने विरोध किया था, बहुगुणा जी का विरोध करते थे जब वे नामिनेटेड चीफ मिनिस्टर थे यू० पी० के । छोडिये इन बातों को, दर्शन करना चाहते हैं तो दर्पण में भी देखिये : . . . **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी) : अभी जो आनरेबल मैम्बर साहब थे, वह कहां से आये, कैसे आये, नदी का मुह भी कभी देखना है नहीं । अभी ऐसा ही चलाना । देखना हो तो गाली मत देना । "ऋषि का कुल और नदी का मूल कभी पूछना नहीं ।"

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : ठीक बात है। मैं कह रहा था कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, कुछ उनके विचार हैं, आर्थिक विचार हैं, सामाजिक विचार हैं, राजनीति विचार हैं, सांस्कृतिक विचार हैं, वह देश के अन्दर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, और सांस्कृतिक विचारों का द्वंद्व देश में चलाना चाहते हैं और उनको पैसे के अभाव के कारण अवसर नहीं मिल पाता है, तो अगर सरकार के जरिये उन को प्रेस चलाने के लिये, कुछ अनुदान मिलेगा तो वह अपनी उस राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विचारधारा को हिन्दुस्तान की आम जनता तक पहुंचाने का काम कर सकेंगे, इसको इस दृष्टि से लिया जाये । जहां पोलिटिकल पार्टी में पैसे देने का सवाल है, तो आप प्रेस कैसे निकालेंगे, कैसे आपकी नीति, बनेगी, क्या बनेगी यह एक अलग प्रश्न है । लेकिन मुख्य रूप से जो अभी हिन्दुस्तान में जितने बडे बडे घरानों के द्वारा प्रेस चलाये जाते हैं वे बडे घराने अपने प्रेसों के द्वारा और अपने अखबारों के द्वारा विरोधी पार्टी की नीतियों को मसलने का काम भले ही करते हों सरकार के साथ रह कर, लेकिन सरकार की नकेल को अपने हाथ में रखने के लिये सरकार को टाइट करते रहते हैं मात्र इसलिये कि सरकार उन के साथ मुलामियत के साथ व्यवहार करे और इस लिये वे सरकार की कुंजी को घुमाने का काम भी करते रहते हैं और जब सरकार उनके साथ नरम हो जाती है तो उन का प्रेस भी सरकार के लिये नरम हो जाता है और वे सरकार की प्रशंसा अपने अखबारों में छापने लगते हैं और जब सरकार न के प्रति गरम हो जाती है तो उन की लेखनी भी सरकार के लिये गरम हो जाती है । इस में इन रिपोर्टरों को कुछ कहना बेकार है जो अखबार में कुछ लिखते रहते हैं । उनकी बात मैं यहां नहीं कहा रहा हूं, लेकिन जो अखबार निकालने वाले, उनके मालिक हैं, और जिन के नियंत्रणमें वे प्रेस चल रहे हैं मैं यहां उन की बात कह रहा हूं । मैं मोटा मोटी कहना चाहता हूं । कि इस बिल के जरिये जो दो मुख्य उदेश्य झा जी ने हासिल करना चाहे उनमें सरकार के हाथ को मजबूत करने का जो सवाल है, अभी इस बात को इस देश

[श्री हुक्मदेव नारायण यादव]

में न चलाया जाये और इस बात को बसन्त साठे जी उठा सकते थे, लेकिन हम लोगों की तरफ से यह बात हो नहीं सकती है और हम इसके लिये अभी सोच नहीं सकते । हां, छोटी छोटी पार्टियों के अखबारों को सहायता देना ताकि वे अपने विचारों को सही ढंग से प्रसारित कर सकें इस मामले में सरकार को उदारता बरतनी चाहिए और उनके लिये सरकार की तरफ से अधिक सहायता और अवसर मिलने चाहिएं । इस से देश का भला होगा, अधिक विचारों का प्रचार और प्रसार होगा और हिन्दुस्तान में नये-नये विचार पनपेंगे और फैलेंगे और हिन्दुस्तान के विचारों के समुद्र में आप को नये-नये रंगीन कमल खिलाने का विचार करना चाहिए । उन कमलों का पंखुड़ियों को तोडने का प्रयत्न आप को नहीं करना चाहिए ।

श्री नरेन्द्र सिंह (उत्तर प्रदेश) : उप-सभाध्यक्ष महोदय, यह प्रैस (प्लांनिग ऐंड फ्रीडम) बिल हमारे मित्र शिव चन्द्र झा जी ने पेश किया है । शिव चन्द्र झा जी मेरे बड़े नजदीकी मित्रों में से हैं । मैं उन की नीयत पर कोई शक नहीं करता और सदन के बाहर भी शक करने का सवाल नहीं है । हम बाहर और भीतर एक ही तरह से बोलते हैं । नियत पर शक करने का कोई सवाल नहीं इसमें मैं नहीं मानता, लेकिन ऐसा लगता है कि यह जो बिल है यह बिलकुल कन्फ्यूज्ड सा है और इस को तैयार करते समय हमारे झा साहब के दिमाग में कोई स्पष्ट बात नहीं रही । यह बिल जैसा कि यह बिल के उद्देश्य में कहते हैं और जैसा झा साहब का कहना है और जो बिल के प्राविजन्स हैं वह सेल्फ कान्ट्रडिक्टरी हैं । एक तरफ तो हमारे झा साहब कहते हैं कि प्रेस की आजादी होनी चाहिए, पूरे तौर से प्रेस आजाद होना चाहिए और दूसरी तरफ कहते हैं कि सरकारी नियंत्रण होना चाहिए और वह सरकारी नियंत्रण के बारे में कहते हैं कि जब 10 हजार उसका सर्कुलेशन हो जाये तो सरकार को, उसे ले लेना चाहिए । मतलब यह है कि जब तक वह बढ़े तब तक तो कोई बात न हो लेकिन जब उस का दस हजार का या उस से ज्यादा का सर्कुलेशन हो जाये, तो उस को सरकार ले ले । ऐसा लगता है है कि बहुत कन्फ्यूज्ड स्थिति में झा साहब ने इस बिल को फ्रेम किया है, इस बिल को कांस्टीट्यूट किया है । मैंने जैसा पहले कहा, मैं उन की नीयत पर शक नहीं करता । अभी हमारे मित्र पी० एन० सुकुल साहब ने करीब-करीब सारी बातें कह दी हैं । उन को मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन उस में दो,-तीन बातें और ऐड करना चाहता हूं । चूंकि हमारे भाई हुक्मदेव जी ने एक बात उठायी और उनका कहना है कि यह प्रेस सरकार को नहीं दिया जाना चाहिए और वह बार-बार इशारा करते रहे हमारे मंत्री श्री बसन्त साठे जी और सरकारी पक्ष के लोगों की तरफ, सरकार की तरफ, क्योंकि हुक्मदेव जी को एक खतरा है कि यह और उन की पार्टी तो शासन में कभी आने वाली नहीं है । लिहाजा सरकार के हाथ में कोई ऐसी ताकत नहीं दी जानी चाहिए।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : खतरा तो यह है....

श्री नरेन्द्र सिंह : इस बात का जरा भी खतरा नहीं है । जो विरोधी पार्टी हैं.. (**व्यवधान**) मैं भी एक जमाने में उनका अंग था । वह विरोधी पक्ष जो अब कभी भी सत्ता में आने वाला नहीं है और इस गर्ज से विरोधी पक्ष में निराशा है, फ्रस्ट्रेशन है । हमारे विरोधी

पक्ष के मित्र जो बात कहते हैं उससे उनकी निराशा की अभिव्यक्ति होती है, निराशापूर्ण वातावरण में वह बात करते हैं ।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : आपके यहां के कुछ मंत्री हमारी पार्टी के थे । हमारे साथी कल्पनाथ राय भी हमारी पार्टी के थे । **(व्यवधान)**

संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : मैं तो समाजवादी पार्टी में था ।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : हम दोनों मिलकर नारा लगाते थे ।

श्री नरेन्द्र सिंह : हमारे मित्र हुक्मदेव नारायण यादव जी ने प्रकाशन विभाग के बारे में कहा कि वह अच्छी पुस्तकें नहीं छापता । मैं समझता हूं कि प्रकाशन विभाग की सूची मंगा कर हुक्मदेव जी ने नहीं देखी । अगर सूची मंगाकर वह देखें तो अच्छी किताबें, अच्छा साहित्य और बहुत अच्छी जानकारी हमारे प्रकाशन विभाग की तरफ से प्रकाशित होती हैं । बहुत से लोगों को इसको पढ़ने की फुर्सत नहीं है । जब पढ़ने की फुर्सत नहीं है तो एक मिनट में कह कर टाल देते हैं, कह देते हैं कि प्रकाशन विभाग कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है ।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : यह मैंने नहीं कहा । मैंने कहा है कि किताबें वर्षों से नहीं छपी हैं । मैंने यह कहा है कि वह काम ठीक से संभाल नहीं रहे हैं ।

श्री नरेन्द्र सिंह : आपको मैंने बिल्कुल इन्टरप्ट नहीं किया । आप मेरे को बार-बार इन्टरप्ट कर रहे हैं ।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : मैंने उनकी किताबों की प्रशंसा की है और आप कह रहे हैं मैंने निन्दा की है ।

श्री नरेन्द्र सिंह : मेरे मित्र हुक्मदेव नारायण जी कह रहे थे . . . .

एक माननीय सदस्य : आप उनका नाम क्यों लेते हैं ?

श्री नरेन्द्र सिंह : वह मेरे मित्र हैं नाम तो आएगा ही । उन्होंने धन के बारे में कहा था । इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि समाचार पत्र निकालना कोई आसान काम नहीं है । पैसा भी हो तब भी आसान काम नहीं है । 5 लाख रुपया तो अलग चीज है 77-77 लाख रुपया जमा हुआ ट्रस्ट में, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, हम सब लोगों ने इकट्ठा करके दिया था । 77 लाख रुपया जमा है लेकिन अखबार ठीक तरह से नहीं निकल रहा है । सब लोगों के सामने है, सब जानते हैं ।

श्री कल्पनाथ राय : निकल तो रहा है ।

श्री नरेन्द्र सिंह : कभी निकलता है, कभी नहीं निकलता । इसका वास्ता रुपये से नहीं होता । इसका वास्ता होता है उद्देश्य से । **(व्यवधान)** सवाल है उद्देश्य का और सवाल है डैडीकेशन का । जो डैडीकेशन से काम करना चाहते हैं वे उसमें सफलता प्राप्त करते हैं । एक बात साफ तौर से कहना चाहता हूं कि बहुत से समाचार पत्र निकले । मैं इसके खिलाफ नहीं हूं लेकिन जो चौपतिया, चार पन्नों का अखबार निकलता है किसी को ब्लैकमेल करने के लिये, किसी को खुश करने के लिये किसी से दो सौ, ढाई सौ छपवा लिये और इससे उनका रजिस्ट्रेशन भी बना

[श्री नरेन्द्र सिंह]

रहता है, इस तरह से समाचार-पत्रों से इस देश का कल्याण होने वाला नहीं है । इस तरह के समाचार-पत्रों की कल्पना नहीं करनी चाहिये । इस तरह के समाचार-पत्रों के बारे में सोचना भी एक गुनाह है । एक बात और मैं कहना चाहता हूं सरकार उसके लिये पैसा क्यों दे । अगर कोई पार्टी अखबार निकालना चाहती है तो पैसा इकट्ठा करे और उससे अखबार निकाले । मेरे भाई शिव चन्द्र झा जी ने स्वयं ही कहा है कि उनकी पार्टी एक अखबार निकालती है उसकी कोई पढ़ता नहीं है । तो उसका हश्र क्या होगा । मैं पूछना चाहता हूं अपने मित्र झा साहब से कि 5 लाख, 10 लाख अमाउंट भी हो, जो जनता का पैसा है उसको बरबाद करने के लिये या उसको बरबाद करने की बात वह क्यों सोचते हैं ? ऐसा उन्हें नहीं सोचना चाहिये । यह राष्ट्रहित में नहीं है । इस तरह की बात नहीं सोचनी चाहिये जिससे जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा बरबाद हो । इसमें बहुत से प्रोविजन्स हैं इसमें 10 धाराएं हैं । इन तमाम तरीकों से हमारे झा साहब ने यह कहने की कोशिश की है कि इसमें किस तरीके से प्लानिंग किया जाये । उन्होंने कहा कि इसको प्लानिंग कमीशन ले ले । एक प्लान्ड प्रेस की कल्पना उन्होंने की है । लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, उनकी कल्पना बिलकुल अधूरी है, उनकी कल्पना बिलकुल कनफ्यूज्ड है । उसमें कोई स्पष्टता नहीं है । मैं झा साहब से यह कहूंगा कि वे इस पर विचार करें कि क्या इस बिल से कोई कल्याण हो सकता है ? मैं समझता हूं कि बिलकुल नहीं हो सकता है ।

हमारे श्री पी० एन० सुकूल जी ने कहा कि इस बिल को वेस्ट पेपर बास्केट में डाल दिया जाना चाहिए । लेकिन मैं झा साहब से कहना चाहूंगा कि उन्होंने इसको बनाने में बड़ी मेहनत की है । इसलिए वेस्ट पेपर बास्केट में डालने के बजाय अगर वे इसको विदड्रा कर लें तो अच्छा रहेगा...**(व्यवधान)** । समय और पैसा तो खर्च हो गया । सरकार का पैसा भी खर्च हो गया और इतना समय भी खर्च हो गया । इस बिल पर इतना डिसकशन हुआ । इसलिए मैं अपने मित्र से यह निवेदन करूंगा कि इस बिल को वे विदड्रा कर लें और फिर उसके बाद विचार करें कि जो मौजूदा व्यवस्था है उस व्यवस्था में किसी और विधेयक की आवश्यकता है या नहीं ।

मान्यवर, इस वक्त समाचार-पत्रों के बारे में चर्चा करने का मौका मिला है । यहां पर सरकार की ओर से मदद करने की बात भी आई है । हमारे देश में समाचार देने वाली जो एजेंसियां हैं उन पर कुछ कहने का हमें अवसर मिला है । इस अवसर का लाभ उठाते हुए, आज हिन्दुस्तान समाचार की क्या स्थिति है, उस पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं । इस समय दो अंग्रेजी समाचार एजेंसियां हैं और दो लैंग्वेज एजेंसियां हैं । हिन्दुस्तान समाचार को सरकार पैसा देती है । करीब 30 लाख रुपये उसको दिये जाते हैं । यह काफी बड़ा एमाउन्ट है । लेकिन उसकी स्थिति क्या है ? वहां पर स्थिति यह है कि प्रोविडेन्ट फण्ड का पैसा भी इम्प्लाइज के हिस्से में नहीं डाला गया है । तीन-चार महीनों से

वहां के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली है । सरकारी मदद के बावजूद भी यह एजेन्सी नहीं चल पा रही है । उस सदन में भी इस विषय पर चर्चा हो चुकी है और यह कहा गया है कि हिन्दुस्तान समाचार एजेन्सी की व्यवस्था को ठीक किया जाना चाहिए । हमारे वसन्त साठे साहब यहां पर बैठे हुए हैं । मैं सदन के माध्यम से उनसे यह मांग करना चाहूंगा कि सरकार का पैसा जो हिन्दुस्तान समाचार को दिया गया है उसकी जांच कराई जाये और इस बात का पता लगाया जाये कि वह पैसा सही तरीके से खर्च किया गया है या नहीं। अगर उस पैसे का दुरुपयोग किया गया है तो सख्त से सख्त कार्यवाही उन लोगों के खिलाफ की जाये जिन्होंने इस पैसे का दुरुपयोग किया है । यह मेरी मांग है । एक बात मैं और कहना चाहूंगा । हमारे मित्र श्री पी० एन० सुकूल जी ने 'नेशनल हेराल्ड' का जिक्र किया । हमारे देश में कई पेपर पार्टी के पेपर हैं । लेकिन मैं यह साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि 'नेशनल हैराल्ड' पार्टी का पेपर नहीं है। 'नेशनल हैराल्ड' का हमारे देश की आजादी की लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है । हिन्दुस्तान की आजादी में जो महत्वपूर्ण रोल इस पेपर का रहा वह बहुत बड़ा है । यह किसी पार्टी का पेपर नहीं है । यह राष्ट्र का पेपर है ।

अन्त में मैं अपने मित्र से कहूंगा कि वे इस बिल को वापस ले लें और उसके बाद सोचें, कुछ मंथन करें कि अगर कोई अच्छी बात उनके दिमाग में आए तो उसको संसद् के सामने पेश करें । इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का विरोध करता हूं और आपने मुझे जो बोलने के लिए समय दिया है, उसके लिए धन्यवाद देता हूं ।

श्री राम नरेश कुशवाहा (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं झा जी को साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इस विषय पर चर्चा छेड़ दी । लेकिन मैं उनसे कहना चाहूंगा कि दो बातों को दृष्टि में रखकर उन्होंने यह विधेयक पेश किया है । एक तो प्रेस के मजदूरों का शोषण होता है, इसलिए उन्होंने उसकी दवा राष्ट्रीयकरण सुझा दी अर्थात सरकार को प्रेस को अपने हाथ में ले लेना चाहिए । और दूसरे राजनैतिक दलों को पैसा दे दें ताकि वे अपने विचारों का प्रचार कर सकें । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक प्रेस को ले लेने का सवाल है यह अगर किसी भी तरीके से सरकार के हाथ में जाता है तो यह बहुत बुरा है । मैं तो समझता हूं कि अगर साठे जी की जगह मैं होता और सोचता कि मैं जिन्दगी भर यही रहूंगा तो मैं इस प्रस्ताव को बिना बहस कबूल कर लेता क्योंकि सरकार के हाथ में ये पूरा एकाधिकार दे रहे हैं, इस विधेयक के द्वारा कि वह जिस तरह से चाहें हमारी हजामत बनाया करें । पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मजदूरों को, जिन को दृष्टि से रखकर राष्ट्रीयकरण किया गया है, हम लोग भी बहुत बड़े नारे लगाते हैं कि राष्ट्रीयकरण कर दीजिये लेकिन इस राष्ट्रीयकरण का नतीजा क्या हुआ ? जो उद्योग सरकार के हाथ में हैं क्या उनमें बिना मूल्य बढ़ाये कहीं कोई मुनाफा हुआ है ? उद्योग का घाटा पूरा करने के लिये माल के दाम बढ़ाये जाते हैं और पूंजीपति दोहरा लाभ कमाते हैं । क्यों हमारे कारखाने घाटा लगाते हैं और क्यों पूंजीपतियों के कारखानों में हर हालत में मुनाफा होता है ? इस राष्ट्रीयरण में मैं केवल एक बात समझता हूं कि वहां नौकरी पक्की, बढ़ते काम से छुट्टी और माल अपना । यानी जो भी माल पैदा हो, हमारा है;

[श्री राम नरेश कुशवाहा]

नौकरी पक्की हो गई, जब सरकार ने ले लिया तो नौकरी पक्की हो गई, कोई निकाल नहीं सकता और अगर निकाला गया तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से लौट आयेंगे । तनख्वाह शैड्यूल के मुताबिक हर साल बढ़ती जायेगी, लेकिन काम बिल्कुल नहीं करेंगे । काम से भी छुट्टी हो जायेगी । अगर खुदानाखास्ता कोई माल पैदा हो गया तो माल भी अपना है और सरकार भी अपनी है । आज राष्ट्रीयकरण में भ्रष्टाचार और निकम्मापन व्याप्त है । माननीय सदस्य जो यह प्रस्ताव लाये हैं वे इस पर जरा गौर से सोचिए । मैं नहीं समझता कि यह काम होना चाहिए । समाजीकरण अच्छा है । हम लोग नारा लगाते थे पहले, कल्पनाथ राय जी भी नारा लगाते थे कि :

"मिल के मालिक मजदूर हों,
खेत मिले किसानों को ।"

लेकिन क्या राष्ट्रीयकरण से मजदूरों को मूल्य मिल जाता है ? नहीं मिलता । मजदूर कहां मालिक होता है । मजदूर तो मालिक तब बनेगा जब कि बराबरी का सांझीदार आप उसको प्रबन्ध में बनाओगे, सरकार, मिल मालिकों और मजदूरों तीनों के बराबर प्रतिनिधि होंगे । इस तरह से मैनेजमेंट कमेटी बनाइये और उसमें बहुमत का जो फैसला हो उसको मानें तो तब मैं समझूंगा कि मजदूर मालिक हो गये। आपको समाजीकरण करना पड़ेगा, राष्ट्रीयकरण मैं समझता हूं कि हमारे देश में फेल हो चुका है परन्तु डर के मारे कोई नहीं बोलता क्योंकि इस पर उसको प्रतिक्रियावादी कह दिया जायेगा अगर हम इसके खिलाफ बात कहेंगे । लेकिन मैं कहता हूं कि सरकारीकरण और राष्ट्रीयकरण के बजाय आप समाजीकरण का काम करें। उससे हमें लाभ मिल सकता है । आप घाटे और नफे में मजदूरों को साझेदार बना दें । घाटा हो तो बांटे और नफा हो तो बांटें । तब उत्पादन कभी नहीं घटेगा । मैं समझता हूं कि यह जो मजदूरों का शोषण होता है पूंजीपतियों द्वारा इसको रोकने की जरूरत है । जिस तरह से भी रोकें इसको रोका जाये । इसको दृष्टि में रखकर, नेकनीयती से माननीय सदस्य ने पत्रकारों का शोषण रोकने के लिये सरकारीकरण की योजना का सुझाव दिया है । लेकिन मैं समझता हूं कि यह इसका इलाज नहीं है । आज अभी हमारे हुकमदेव नारायण यादव जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो प्रेस है यह ठीक है कि वह पूंजीपतियों का है लेकिन यह प्रेस कभी कभी सरकार से नाराज होता है तो सरकार के खिलाफ भी लिखता है । वह यह सब करता है अपनी प्रेस की शक्ति से और सारी चीजें, सरकार की खुशामद से भी सुविधा लेता है और विरोध करके भी सुविधा लेता है । आज इसी प्रेस ने यह वातावरण बनाया है कि सारे के सारे राजनैतिक लोग एकदम भ्रष्ट हैं और बाकी सभी लोग ईमानदार हैं । मैं यह नहीं कहता कि इधर के या उधर के मैं आपसे केवल यह कहना चाहता हूं कि पूंजीपति और नौकरशाही जो है वह इस देश में इस तरह का वातावरण बना रही है । ताकि राजनीतिक लोगों पर से लोगों का विश्वास हटता जाए और तब उनकी बन आए । तो यह प्रेस भी बहुत खतरनाक है लेकिन उसका कोई इलाज तो ढूंढना पड़ेगा मिल बैठ कर के ढूंढना पड़ेगा, किसी को एकाधिकार देने से काम नहीं चलेगा और कोई भी सरकार जो गद्दी पर बैठेगी वह चाहेगी कि हमारे हाथ में प्रेस है तो हमारी बात करे । आल इंडिया रेडियो सरकार का है । हम लोग यहां संसद् में चिल्लाते हैं, चीखते चिल्लाते

हैं कितना निकलता है । बहुत हुआ तो रेडियो का संवाददाता नाम गिना देगा बाकी सारी पब्लिसिटी सरकार की होगी । तो हर सरकार यह चाहती है कि वह अपना प्रचार करे, अपने मुंह मियां मिट्ठू बने । नरेन्द्र सिंह जी ने कहा। इन लोगों का विश्वास है कि यह लोग वहां से यहां नहीं आएंगे । भाई साहब हम अभी तो नहीं जा सकते लेकिन मैं समझता हूं कि कोई असंभव नहीं है कि आप इधर चले आवें और हम उधर चले जाएं । हम यह मान कर कहते हैं यह बात कि चाहे जो कुछ भी हो हम भी वहां रहे तो हमारे हाथ में नहीं मिलना चाहिये । क्योंकि आज जो आपके पास है वह हमें दे दिया जाए तो हम आपकी हजामत बनाना शुरू कर दें और आज आप बनावें तो यह तो मानव स्वभाव है । मैं नहीं समझता हमारे या आपके हाथ में एक दूसरे की हजामत बनाने का छुरा दे दिया जाए । यह तो समाज में रहना चाहिये ।(व्यवधान) हलाल करने के लिए भी छुरा क्यों किसी को दिया जाए, चाहे यह हमारे हाथ में हो या आपके हाथ में हो । अगर इस देश में लोकतंत्र को चलाना है तो विचारों की स्वतंत्रता रखनी पड़ेगी । अगर पूंजीपतियों को आपको रखना है मैं यह मान कर चलता हूं कि हम संयुक्त अर्थ-व्यवस्था को चलाएंगे तो सब को अपनी बात कहने का अधिकार है और हम को भी अपनी बात कहने का अधिकार है । जो जिस विचार को चाहता है वह फैलाए । हम 80–85% जनता के प्रतिनिधि हैं लेकिन हम उनको नहीं समझा पाते हैं, वे अपने भले की बात नहीं समझ पाते हैं अगर नहीं समझा पाते हैं तो वे यदि कोई गलत फैसला करते हैं उसमें दोष किसका है ? हमारी, आपकी सारे देश की जिम्मेदारी है । इस देश की जनता को प्रबुद्ध हमने नहीं किया कि वे अपने हित का फैसला कर सकें ।

मेरा आपसे निवेदन है कि इस मसले पर बिल्कुल हमको आपको खुले दिल से विचार करना चाहिये कि किसी भी सरकार के हाथ में कोई हथियार ऐसा नहीं मिलना चाहिये जिसका दुरुपयोग हो । मैं झा साहब को कहूंगा कि आप इसको समझें । दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह कहना चाहता हूं कि सरकार रुपये दे । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसमें इनकी दो भावनाएं नहीं हैं । एक तो हुक्मदेव जी ने कहा मैं यह दोहराना नहीं चाहता हूं । हमारे साधन सीमित हैं । हम अपने विचारों का प्रचार नहीं कर पाते । अगर सरकार कुछ मदद करे तो कुछ किया जा सकता है । लेकिन सरकार कोई मदद क्यों करे । जब केवल सिद्धांत तक ही प्रचार करना हो तो कोई उदार सरकार मदद कर सकती है लेकिन जब व्यक्तिगत आक्षेप की बात कहे तो कोई भी सरकार चाहे हम हो या आप हों इसके लिए कोई पैसा नहीं देगी । मेरा आपसे यह कहना है कि चुनाव आयोग के लिए चुनावों के लिए चाहे जितनी मदद दी जाए पार्टी के लाभ के लिए देनी चाहिये । उस रिकोग्नाइज्ड पार्टी के प्रेजीडेंट और सेक्रेटरी के लिए गाड़ी में चलने का पास दे दें और कुछ दे दें उनको कार्यालय दे दें, कोई पार्टी प्रेस चलाना चाहता है तो उसको जमीन दे दें, कर्जा दे दें, उसको विज्ञापन दे दें सारी चीजें दे दें, सारी सुविधाएं दे दें लेकिन सरकार के भरोसे पर सरकार के पैसे से कोई भी राजनीतिक दल सरकार को हटा नहीं सकता और जिसका पैसा लेंगे उसका भुगतान करना पड़ेगा नहीं गायेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा : जैसे हमारी सरकार आज पूंजीपतियों से पैसा लेती है इसलिए हर काम पूंजीपतियों के पक्ष में ही जाता है । हल्ला जरूर करती है कि हम गरीबों के पक्ष में हैं, हम गरीबी को मिटाना चाहते हैं, अशिक्षा मिटाना चाहते हैं, दरिद्रता मिटाना चाहते हैं जो लोग किसी लायक नहीं हैं उनको ऊपर उठाना चाहते हैं । लेकिन कितना आपने उठाया है, कितना उसके अधिकारियों को खत्म किया है ? कर नहीं पाये । तो अगर कोई भी राजनीतिक दल सरकार से पैसा लेकर प्रेस चलायेगा तो जितनी प्रखर आलोचना और तेजस्विता उसमें होनी चाहिए वह हम नहीं ला पायेंगे । इसलिए

[श्री राम नरेश कुशवाहा]

मेरा आपसे अनुरोध है झा साहब कि आप इस विधेयक से सरकार के हाथ में वही हथियार दे रहे हैं कि आ बैल मोहि मार। तो आ बैल मोहि मार वाली कहावत चरितार्थ न करें और इस विधेयक पर आप जोर न दें। चर्चा तो हो, इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए जितनी हम और आप कर सकें ; अच्छा है।

श्री विट्ठल भाई मोतीराम पटेल (गुजरात) : उपसभाध्यक्ष महोदय, आज सुबह आने के बाद मुझे पहला मौका इस प्रेस बिल पर बोलने के लिए मिला है। श्री झा साहब ने यह जो बिल पेश किया है और इसमें जो 'फ्रीडम' शब्द यूज किया है इस पर मुझे ताज्जुब होता है। अगर सरकारी प्रेस बनने से अखबार वालों को आजादी मिलेगी तो यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। मैं 30 साल से इस प्रोफेशन में हूं, 30 साल से मैं जर्नलिस्ट हूं। जब प्राईवेट अखबारों को आजादी नहीं मिलेगी तो सरकारी वालों को कहां मिलेगी। झा साहब जरा अखबार वालों से भी पूछिए कि उनको आजादी अब कहां है और सरकारी प्रेस होने से उनको और आजादी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कई चीजें ऐसी हैं जो झा साहब खुद प्रेस के बारे में जानते नहीं हैं। अब ठीक है आप सरकार को प्रेस के बदले ऐसा कुछ बंदोबस्त करें कि आज जो प्राईवेट हाथों में प्रेस है उसमें थोड़ा सा जर्नलिस्टों को रखें, जेन्यूइन जर्नलिस्टों को। क्योंकि अब तो क्या है, न्यूज पेपर्स में क्या बात है कि मालिक लोग एडीटर बन जाते हैं, वे अपनी पालिसी बनाते हैं, जर्नलिस्टों को तो कोई अधिकार होता नहीं है। तो ऐसा कुछ रास्ता निकालने की बात करें कि कुछ क्वालीफाईड आदमी एडीटर बन सकें। आज जो मालिक हैं वे जिस भाषा में अखबार निकलता है उस भाषा का एक पैराग्राफ भी नहीं लिख सकते हैं। फिर भी एडीटर का नाम छपता है, वह तनख्वाह भी लेता है, पालिसी भी तय करता है। ये सब चीजें मिटाने के लिए आप कुछ करते तो ठीक होता। लेकिन सरकारी प्रेस बनाने की बात से सब हल हो जायेगा, यह बात मैं नहीं मानता हूं। इसलिए कुछ ऐसा रास्ता निकालिए, कुछ कोड आफ कन्डक्ट बनाईये अखबारों के लिए तो बात ठीक है। जो सही जर्नलिस्ट हैं जो पसीना बहाता है सारे देश में घूम घूम कर न्यूज कलेक्ट करता है उनकी आजादी की बात की जाये तो भी ठीक है। जो आज फ्रीडम आफ प्रेस की बात की जाती है वह तो सिर्फ मालिकों की आजादी की बात होती है। जो सही अखबार वाले होते हैं उनको आजादी तो बहुत कम है। कई अखबार ऐसे हैं जहां बांडेड लेबर की तरह से जर्नलिस्ट काम करते हैं। उनको छुड़ाने के लिए कुछ बात करें तो ठीक है। यह तो क्या है कि प्राईवेट मालिक के हाथ से आप ब्यूरोक्रेसी के हाथ में डाल देंगे उनको। सरकार मालिक हुई मतलब ब्यूरोक्रेसी मालिक हुई और वहां सब आई ए०एस० कैडर वाले होंगे वे जो हुक्म करेंगे वही होगा। यह बोर्ड वगैरह तो कुछ नहीं चलता। हमने तो सरकारी आफिसों में बोर्डों में देखा है। वहां भी जो आई०ए० एस० कैडर वाले होते हैं जो कहते हैं वही सही होता है। हमारे मिनिस्टर साहब उन्हीं का नोट पढ़ते हैं प्रैक्टिकल नहीं करते हैं कई बार। इसलिए अखबार को आजादी की जो बात है वह इसको सरकारी बनाने से नहीं होगी। इसके लिए कोई और रास्ता सोचिए, कोड आफ कन्डक्ट बनाइये, जो रीयल जर्नलिस्ट हैं उनको बिठाईये। अभी जो अखबार चलते हैं वे ज्यादातर प्राईवेट हैं, इनका कोड आफ कन्डक्ट बनाइये, इसमें अखबार वालों को रखें, यही आजादी उनके पास रहने दें। आज उनके पास जो आजादी है वही काफी है, वह आजादी कम नहीं है अखबार वालों के लिए। आज भी अखबार वालों को इतनी आजादी है कि वे जो चाहे लिख सकते हैं कोई उसे रोकने वाला नहीं है। झा साहब आप का यह बिल पास होने के बाद कौन सी आजादी उनको मिलेगी यह मेरी समझ में

नहीं बैठता है। उनको ज्यादा आजादी कैसे मिलेगी ? कभी नहीं मिल सकती।

दूसरी बात यह कि वहां भी बोर्ड बनाओ, यह प्लानिंग करो, कुछ भी करो। अखबार चलाना इतना आसान काम नहीं है। प्रेस चलाना भी एक टेक्निकल साईड है। कई लोग ऐसे ही प्रेस लगा लेते हैं परंतु बाद में पछताते हैं। तो प्रेस लगाना भी सरकार का काम नहीं है। सरकारी प्रेस भी अच्छे चलते हैं उनसे, जो प्राईवेट चलाते हैं। यह एक टेक्निकल सब्जैक्ट है, इसमें सरकार न जाये यही अच्छा है। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रेस को आजादी के लिए यह बिल जरूरी नहीं है और कोई सोच विचार कर आप दीजिए तो ठीक होगा।

लेकिन मैंने जो बाकी सुना है, हुक्मदेव नारायण यादव जी वगैरह को सुना अपोजीशन के बारे में—अपोजीशन का काम यही है कि सरकार की हर बात में विरोध करना सरकार को हटाना, वह तो मैं समझता हूं कि अपोजीशन एक तो सरकार की चौकसी करने के लिए हैं, सरकार पर नजर रखने के लिए है, पर हर बात का विरोध करने के लिए नहीं है। जिसको रियल आल्टरनेटिव बनना होगा, उसको कंस्ट्रक्टिव भी बनना होगा।

सरकार की अच्छी बात हो, तो उसको सपोर्ट भी करना होगा। अच्छी बात का विरोध करने से कभी अपोजीशन बनेगी नहीं, कभी आल्टरनेटिव नहीं बनेगी। इस देश में अगर आल्टरनेटिव किसी अपोजीशन को बनाना हो, तो कुछ तो कंस्ट्रक्टिव काम करना ही होगा। उनको सोचना पड़ेगा कि कल हम पावर में आयेंगे, तो क्या करेंगे।

जनता पार्टी जब शासन में थी, तो क्या अखबार की आजादी को उन्होंने छीन तो नहीं लिया था। लेकिन वहां भी कुछ नेपोटिज्म चला था। वहां पर भी कुछ अखबारों को फेवर किया गया था, कुछ को डिसफेवर किया गया था। वह जनता पार्टी के शासन में भी था और यह मामूली चीजें तो रहेंगी ही, जब तक डेमोक्रेसी है, यह चीजें तो रहेंगी ही। लेकिन जनता पार्टी कहें कि हमारे यहां प्रेस फ्रीडम बिलकुल था, कोई गलती नहीं थी, तो यह बात भी गलत है। उस वक्त भी हमने देखा है कि अपने वाले भी अखबार थे, सामने वाले भी अखबार वाले थे, उस जमाने में भी।

तो इसलिए मैं चाहता हूं कि यह बिल आप वापिस ले लीजिए, और बिल ऐसा बनाइये कि जिससे अखबार की आजादी जो आज है वह रहे और जर्नलिस्टों को भी आजादी मिले, जो सही जर्नलिस्ट हैं, मानोपली वालों की नहीं, लेकिन जो अखबार में लिखने वाले हैं, उनके लिए ऐसा कुछ बिल बनाइये, तो मेरे जैसा व्यक्ति आपकी जरूर सपोर्ट करेगा। धन्यवाद।

श्री रामेश्वर सिंह : उपसभाध्यक्ष जी, प्रेस की आजादी के संबंध में शिव चन्द्र झा जी ने... (**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी) : रामेश्वर सिंह जी आपके दस मिनट ही हैं।

श्री रामेश्वर सिंह : मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि ऐसी कोई बात इसमें हमको नहीं कहनी है।

उपसभाध्यक्ष (श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी) : ठीक है। अब चलिए भाई।

श्री रामेश्वर सिंह : उपसभाध्यक्ष महोदय, शिव चन्द्र झा जी ने जो प्रेस की आजादी के संबंध में एक गैर-सरकारी विधेयक पेश किया है, उस विधेयक की टैक्निकल चीजों में मैं नहीं जाना चाहता, उसकी बारीकियों में मैं नहीं जाना चाहता।

मैं प्रेस की आजादी में जो कुछ भी देख रहा हूं और साथ ही साथ हमारे पुराने मित्रों में से यह लोग हैं, लेकिन उस जमाने में जब इनकी जवानी की शुरुआत थी, तो समाजवादी दल से संबंधित थे। अब यह पुराने समाजवादी ख्यालात के व्यक्ति हैं और सौभाग्य

[श्री रामेश्वर सिंह]

कहिए, मेरे लिए तो दुर्भाग्य की बात है, लेकिन कल्प नाथ राय जी के लिए सौभाग्य की बात है कि उनके हाथ में आज प्रेस की ताकत है । लेकिन, उपसभाध्यक्ष जी, आप देखें कि आज प्रेस की आजादी है कहां, आज देश में स्वतंत्रता है कहां ?

मैं दो-तीन एक्जाम्पल्ज देकर अपनी बात खत्म करूंगा (व्यवधान) प्रेस में और प्रेस में जिन लोगों का जीवन जुड़ा हुआ है, उन के संबंध में मैं पहले चर्चा करना चाहता हूं । प्रेस में आजादी हो, या न हो, यह तो अभी बाद की बात है, लेकिन जिनका जीवन प्रेस से जुड़ा हुआ है, जो लोग प्रेस से संबंधित हैं, जो लोग प्रेस में काम करते हैं, क्या वे आजाद हैं ?

क्या वे जो सूचनाएं इकट्ठी करते हैं, जो रिपोर्टिंग करते हैं, अखबार के मालिक उसको छापते हैं ? उन का जो दुख-दर्द है, उन का जो पारिवारिक दुख-दर्द है, उनके बाल-बच्चों का जो दुख दर्द है—उन की दवा आदि का इंतजाम, उन के यातायात का माकूल प्रबंध, उनके रहने की व्यवस्था, उनके बच्चों को पढ़ाने का इंतजाम—लेकिन यह देश एक ऐसा अभागा देश है जिस देश में हम रह रहे हैं . . .

श्री कल्प नाथ राय : सौभाग्यशाली है ।

श्री रामेश्वर सिंह : भाग्यशाली है कल्पनाथजी के लिए, क्योंकि वह मिनिस्टर हैं और हो सकता है वह गृह मंत्री हो जाएं, उनकी इच्छा हो प्रधान मंत्री भी बन जाएं, प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी को हटाकर ; हो सकता है उन की इच्छा इतनी बड़ी हो लेकिन इच्छा यह नहीं है । मेरी इच्छा है मुल्क को बनाने की । होल पोलिटिकल लाइफ में, जब कभी मैं अपने 30–32 वर्ष के अपने राजनैतिक जीवन के बारे में सोचता हूं कि मैं कहां खड़ा हुआ हूं ? साठे जी समाजवादियों का साथ छोड़ कर कांग्रेसियो के साथ आए, आज मंत्रिमंडल में हैं, कल्पनाथ राय जी मंत्रिमंडल में है । हमारे छोटे भाई हैं, हम तो प्यार करते हैं । ये भी चले गये । अशोक मेहता चले गये । यह विवाद का विषय हो सकता है । हो सकता है, मैं भी चला जाऊं । इन्सान गिरने लगता है जब कहीं उसको लगता है कहीं फिसलन है । हो सकता है साठे साहब और भाई कल्पनाथ जी मुल्क को बनाने के लिए गए हों । अब आए दिन अखबार में पढ़ते हैं कि हमारे भाई चाहे छोटे-छोटे अखबारों में हो या बड़े-बड़े अखबारों में, जो वहां काम करते हैं, किस तरह मारे जाते हैं । एक पत्रकार की औरत के साथ बलात्कार तक हुआ है पिछले साल । अब आप आगे देखिए जो अखबारों में रिपोर्टिंग करते हैं, रा मैटीरियल इकट्ठा करते हैं और प्रेस को देते हैं उन की हालत यह है । एक व्यक्ति रघुवर सहाय का मैं जिक्र करना चाहूंगा आप देखिये टाइम्स आफ इंडिया ग्रुप—टाइम्स आफ इंडिया, नवभारत टाइम्स और दिनमान जिसके अन्तर्गत है, उसने क्या किया ? रघुवर सहाय एक नितांत शरीफ, नितांत भद्र पुरुष, नितांत डिमोक्रेट, वह अपने क्लब के लिए इस मामले में मशहूर था कि उसकी चिंतन धारा और लेखनी इंडिपेंडेंट होती थी, स्वतंत्र होती थी । मैं साठे साहब से पूछना चाहता हूं, 1977 के पहले जो कुछ भी उन्होंने लिखा और 1977 में हम जब सरकार में आए—हमारे हुक्मदेव नारायण जी यहां बैठे हुए है उन्होंने जिक्र किया कि आज सरकार में आप हैं, कल मैं जा सकता हूं तो नरेन्द्र सिंह जी कह रहे हैं यह सरकार में कभी आने वाले नहीं हैं, तो यह नरेन्द्र सिंह जी के लिए हो सकता है लेकिन मैं नरेन्द्र सिंह जी को याद दिलाना चाहूंगा, 1967 में 9 राज्यों में आपकी सरकारों की बधिया बैठ गई थी और आपने सरकारों पर कब्जा कर लिया था । सन् 1967 भूलिए मत, और फिर 10 वर्ष बाद 1977 में

सम्पूर्ण देश में चुनाव जीत कर इस सदन में और उस सदन में एब्साल्यूट मैजारिटी हासिल कर ली थी। मैं उन लोगों में हूं, मैं बकवास के लिए सदन में नहीं आया। मैं टी०ए०डी०ए० बनाने के लिए नहीं आया हुं। मैं इसलिए आया हूं कि जनता का जो दुख-दर्द है उसको दर्पण में दिखाया जाए, उस आइने में दिखाया जाए जिस से सही तसवीर दिखायी दे। लेकिन यहां हो क्या रहा है? उप-सभाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि पंडित रघुबीर सहाय जी की एक पूंजीपति जो अखबार के द्वारा अपना कैपिटल इस मुल्क में स्थापित करने में सफल रहा है, उसके इशारे पर हटाया गया। हरिदास मुन्द्रा इस देश का एक नम्बर का पूंजीपति बनने जा रहा था। दिनों-दिन रातों-रात वह हिन्दुस्तान में बिडला की टक्कर में आगे आने वाला था, लेकिन वह क्यों फेल हो गया क्योंकि उसके हाथ में अखबार नहीं था, लेकिन हरिदास मुन्द्रा मुझसे नहीं, मैं उस श्रेणी का व्यक्ति उस समय नहीं था, लेकिन हमारे नेता डा० राम मनोहर लोहिया जो अब इस धरती पर नहीं हैं, जिनका स्वप्न हमारे सामने है आता है तो हमारी समझ में आता है कि अब जनता का सही आदमी इस धरती पर नहीं है, आखिरी व्यक्ति जो इस देश में आचार्य कृपलानी से वह चन्द रोज पहले हमारे पास से उठ गये, हरिदास मुद्रा ने उन से कहा कि डाक्टर साहब काश हमारे हाथ में अखबार होता। मैंने जिन्दगी में सबसे बडी दौलत पैदा की, मैंने बेहद पैसा कमा लिया और 5 साल में देश में बिड़ला को मात देने की कल्पना करली थी, इस देश में सबसे बडा पूंजीपति में बन जाऊंगा और सारा साम्राज्य हमारे हाथ में आ जायेगा। लेकिन हम एक गलती कर गये। वह क्या थी ? हमने अखबार स्थापित नहीं किया। अगर हमने अखबार स्थापित किया होता तो हम जवाहर लाल नेहरू जी का फोटो लाल बहादुर शास्त्री का फोटो, और मंत्री मंडल में जो लोग थे, उनका फोटो छाप कर इस देश में बांटते तो हम बिडला पर कब्जा करके बैठे रहते। लेकिन हमारे हाथ में अखबार नहीं था। बिडला साहब के हाथ में अखबार था। टाटा साहब के हाथ में अखबार था। डालमिया के हाथ में अखबार था। उन्होंने हरिदास मुन्द्रा को मात दे दी।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस लिये यह कह रहा हूं कि साठे साहब से मैं पूछना चहाता हूं कि आप ईमानदारी से बताइये, जनता की इस अदालत में आप बैठे हुए हैं, इस से बडी अदालत नहीं है, देश की सर्वोच्च अदालत में जहां पर आप बैठे हुए हैं, आपने टाइम्स आफ इंडिया ग्रुप को दबाव दिया कि रघुबीर सहाय सरकार के खिलाफ लिखता रहा है, इस को वहां से हटाओ। अशोक जैन ने रघुबीर सहाय से कहा कि तुम अपनी लेखनी को कम करो तुम्हारी लेखनी की जो ताकत है उससे सरकार हमसे कुपित होती जा रही है हमारी सारी इंडस्ट्री को सरकार नेशन-लाइज कर लेगी और सारी इंडस्ट्री को सरकार पैरालाइज कर देगी। श्रीमन्, रघुबीर सहाय को कहा गया तो रघुबीर सहाय ने कहा कि नहीं, मेरी जो जहनियत है, मेरा जो रक्त है, मेरे शरीर में जो खून है, भले ही आप हमें नौकरी से निकाल दो, लेकिन मेरा जो मस्तिक है, जो मेरा करेक्टर है, इस करेक्टर के विपरीत मैं नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि नवभारत टाइम्स में आप जाकर एडिटिंग का काम करों, आप दिनमान से हट जाओं। इस तरह वह हटा दिये गये। यह आजादी है ? यह प्रेस की आजादी है मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं आपको बतलाना चाहता था लेकिन मेरे

[श्री रामेश्वर सिंह]

पास समय नहीं है, मेरी एक अर्जेन्ट मीटिंग है, अपने साथी से मने रिक्वैस्ट किया कि मुझे मीटिंग में जाना है । जाइये मत, साठे साहब फोरन हमारी बात का जवाब दीजिये ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, बहुत अदब के साथ मैं कहना चाहता हूं कि अभी महीने दो महीने पहले से हमारी पार्टी, जिस पार्टी को मैं डिलांग करता हूं, जिस पार्टी का मैं राष्ट्रीय समिति का सदस्य हूं, पार्लियामैन्टरी बोर्ड का मैं सदस्य हूं, उस पार्टी का अखिल भारतीय सचिव हूं उस पार्टी के बारे में उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री ने, और हिन्दुस्तान के जो मंत्रिमंडल के कैबिनेट के लोग हैं, उन्होंने कहा कि चरण सिंह के लोग डकैतों के साथ मिले हुए हैं । हमारे नेता मुलायम सिंह को अखबारों में छपवाया गया कि मुलायम सिंह डकैतों के साथ रहता है ।

4.00 P. M.

कहिये तो मैं पढ दूं, लेकिन समय नहीं है, इस लिये पढ़ना नहीं चाहता । लेकिन छपवाया गया । मैं पूछना चाहता हूं कि यह छपा और हम ने इस को फेस किया। हमने जवाब दिया कि सत्य सत्य है । सच्चाई सच्चाई है । आप कुर्सी पर बैठे हैं यह सत्य है । अगर कोई कहे कि आप चौकी पर बैठे हैं तो यह असत्य है । अगर कोई कहे कि उपसभाध्यक्ष खडे हैं तो यह सत्य है । सत्य है कि आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं, यह सत्य है और इस से कोई हमें डिगा नहीं सकता । हम को यह डिगा नहीं सके । हम को साबित नहीं कर सके कि हमारा डकैतों से संबंध है । लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के भाई का मर्डर हुआ ।

श्री सैयद रहमत अली (आन्ध्र प्रदेश) : यह बार बार इसका जिक्र क्यों करते हैं।

श्री रामेश्वर सिंह : मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया है और जनतंत्र का तकाजा है कि आप अपनी बात कहें, और हमारी बात को हिम्मत से सुनें । आप सौ गाली हमें निकालें हम धीरज से सुनने के लिये तैयार हैं लेकिन आप भी तो गाली के जवाब में हजार गाली सुनने के लिये तैयार रहें । ऐसा होने पर ही जनतंत्र का निर्माण होगा, नहीं तो जनतंत्र का निर्माण नहीं हो पायेगा । उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री हमारी सरकार के मुख्य मंत्री नहीं हैं । उत्तर प्रदेश की सरकार के मुख्य मंत्री को हमने कहा है, बार बार कहा है, लेकिन आपने, आप के अखबारों ने हमारी बात नहीं छापी, हम ने कहा कि तुम एनकाउन्टर करते हो । लेकिन हमारी बात अखबारों ने नहीं छापी । मगर उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के भाई का मर्डर होता है । उस से हमारा कोई मतलब नहीं है, हाथ चाहे किसी का हो, हाथ हाथ है, और पूर चीज जिस अखबार में आती है कि एक सेंट्रल कैबिनेट के मंत्री का नाम है और सेंट्रल कैबिनेट के मंत्री ने डकैतों को प्रश्रय दिया । वहां की पुलिस ने कहा है कि यहां की पोलिटिकल पार्टी ने प्रश्रय दिया है सेंट्रल कैबिनेट के मंत्री को, हम तीन दिन से बोल रहे हैं लेकिन अखबारों ने क्यों नहीं छापा । आप ने अखबारों को मना कर दिया है (व्यवधान)

श्री सैयद रहमत अली : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है ।

श्री रामेश्वर सिंह : बैठो । (व्यवधान)

श्री सैयद रहमत अली : आप के कहने से किसी के बैठने का सवाल पैदा नहीं होता । पार्लियामेंटरी तरीका यह है कि वाइस चैयरमैन साहब ने मुझे इजाजत दी है । तो आप बैठिये ।

उपसभाध्यक्ष (श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी) : आप का क्या प्वाइन्ट आफ आर्डर है ?

श्री सैयद रहमत अली : मैं यह बात अर्ज करना चाहता हूं कि जिस बिल पर यह हाउस गौर कर रहा है उस पर तकरीर करते हुए रामेश्वर सिंह जी ने कहा था कि मैं हाउस का वक्त खराब करने के लिये हाउस में नहीं आया हूं। लेकिन जो यू० पी० के मर्डर का हवाला बार बार पिछले तीन दिन से दोहरा रहे हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि इस बिल से उस वाकये का क्या ताल्लुक है और अगर यह ताल्लुक नहीं रखता इस बिल से तो इस को रेकार्ड में नहीं शामिल किया जाना चाहिए और उन को इस के लिये इजाजत नहीं दी जानी चाहिए ।

SHRI HAREKRUSHNA MALLICK (Orissa); Sir...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI) : Mr. Mallick, you are not concerned with it. I am to give *my* judgment, you please dont give any opinion on this.

For your information, under rule 238 he has not taken any name. If here is any impropriety in what he speaks I can remove it. But there is no impropriety in it. He is speaking on the freedom of press and how press is gagged in Uttar Pradesh. He is speaking and I am just listening and you are also listening. You can reply if you want when your time cornes.

श्री रामेश्वर सिंह : मैं बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूं । श्रीमन्, मैं जानता हूं इस हाउस में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पालिटिक्स नहीं जानते हैं । पालिटिक्स क्या है उनको मालूम नहीं है । जनतंत्र क्या है उनको मालूम नहीं है । जनतंत्र चलाने की क्या व्यवस्था है उनको नहीं मालूम । आपको आंखों में आंसू तक नहीं आते । मैं इतना कह कर बैठ जाना चाहता . . . (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी) : बहुत टाइम ले रहे हैं ।

श्री रामेश्वर सिंह : मैं आगे नहीं कहूंगा । आचार्य कृपलानी की फोटो छपी है गांधी जी और जवाहर लाल जी के साथ । देश की और आपको इस हैसियत में लाने का काम आचार्य कृपलानी जी ने किया है लेकिन आपको शर्म नहीं है । (व्यवधान) मैं अपने आप से भी कहता हूं (व्यवधान) . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): Mr. Rameshwar Singh, you have to conclude. Please take your seat.

श्री रामेश्वर सिंह : वह आदमी मरता है उस आदमी के मरने पर आप आंसू तक नहीं बहाते हैं । राजघाट बनाते हैं, संजय पार्क बनाते हैं, रामेश्वर पार्क बनाते हैं ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI); Mr. Rameshwar Singh, this has no mean ing at all. You are going beyond your __ *(Interruptions).*

श्री रामेश्वर सिंह : ऐसे इंसान के लिये आपके अखबार में कोई जरिया है (व्यवधान) मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI); Mr. Rameshwar Singh, you have tQ conclude now.

श्री रामेश्वर सिंह : मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं । मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर प्रेस की फ्रीडम आपने खत्म की, जैसे कि आपने रेडियो की फ्रीडम खत्म की, मनमाने तरीके से . . . (व्यवधान) इन्टरवीन कराते हैं वह समय दूर नहीं है जब आप हमारी जगह पर बैठेंगे और हम आपकी जगह पर आकर बैठेंगे । (व्यवधान) हम लोग सब कुछ जानते हैं । हमने आपको 67 में हटाया, 1977 में हटाया और मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आने वाले दो-तीन वर्षों

[श्री रामेश्वर सिंह]

में हम कब्जा करेंगे । आपको हटा देंगे । हम आ जायेंगे । आप जनतंत्रवादी नहीं है, आप जनतंत्र के हत्यारे हैं । लोकतंत्र के हत्यारे हैं । आपकी सरकार कोई इंसाफ नहीं करती है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी) : आप खत्म करिये ।

श्री रामेश्वर सिंह : आपकी सरकार में कोई इंसाफ नहीं है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं । अब मैं जा रहा हूं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी) : साठे साहब जवाब देने वाले हैं उसको सुनिये ।

श्री रामेश्वर सिंह : मैं माफी मांग कर जाता हूं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी) : : पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस है आप सुनिये । (व्यवधान) आप गाली देकर चले जायेंगे तो साठे साहब क्या बोलेंगे ।

श्री रामेश्वर सिंह : मीटिंग है मुझे जाना है । ये लोग सुन लेंगे ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): Mr Mallick. You have got only five minutes.

SHRI HAREKRUSHNA MALLICK: Sir, I am thankful to the hon. Chair and I am also thankful to Mr. Rameshwar Singh, who has actually gone out now. Sir, while making a few points on this Bill, which is a very important Bill, I would like to say that this Bill appears to many as if our hon. and esteemed friend here is playing into the hands of certain agencies and that as if this Bill is intended to undermine the freedom of Press. No. This is not the case. I will give you a simple example-If there is a bit of gold, however much you may burn it, it will dazzle more and more. It will never be destroyed in fire. If the real liberty is given to the Press, the liberty will be there and the Press will also be there. As the axiom runs, eternal vigilance is the price of liberty. Not only here in India, but throughout the globe, it is desired that the Press should display eternal vigilance. But in many places, it only displays internal vigilance. There is only a change in the spelling. But thi9 makes a world of difference. As our hon. friend has said, the word 'news' 'NEWS' is actually a coined word, taking the initials from the four directions, namely, north, east, west and south. This means, from all sides, whatever events occur, should be reflected therein. But on many occasions, newspapers have proved to be only viewspapers. This is because, everybody wants to dump their view points on others. Secondly, right from the management up to the reporters, everywhere, there' are faults and faults. Reporters are many. But they know only what not to report. They actually are there to see what not to report. They are there not to see what to report. As we see in many places, they are there only to see what not to report. Rightly so, whatever views we express here in Parliament and in Assemblies, nothing comes out in their pages, as if they are practising a censorship of parliamentary activities in this country. What the Members who make some contribution in the House say, about the Government, the way is functions, the way the different Ministers-respond—that never finds a place in the pages of the newspapers. Therefore in Oriya, there is a proverb which means that radish, whether washed or not washed, sells equally well in the market. The result is that the people in the periphery who exoect so much from and through the newspapers get nothing out of them. All this is practically blacked out. Today

there was a news item, that Dr. Kamleshwar has been thrown out of Doordarshan. I do not know whether the time was really mature that he should go, but it is reported that he had to go because of a conflict with Brahama-chari. The Brahmachari wanted to give discourses through the Television not on Upanishad, Vedanta or Gita, but on mastar-bation and conception. So there was a conflict and he has been thrown out. Such a thing has happened and I hope the hon. Minister will look into it. I am not trying to create a controversy. I only request him to see how best the things can be done.

Here in our country we have given the call everywhere for "Grow More Food", for going in for intensive cultivation. Actually we are seeing intensive paper cultivation. In the press this intensive paper cultivation is going on, beating about the bush and producing nothing. Sir, I am just concluding. We should see that tonnes of paper should not be misused to serve only a few persons' ends. If we see the matrimonial columns we can guess how much money they are making. Do we ever find on any page of the newspaper a little advice on health, a little advice about family planning, or about what happens in Parliament, a little advice about what people should do, or about adulteration? Nothing, no constructive programme, no hint about nation-building is there. Thev are making money, making mischief. Not only there are multi-nationals, but there are nationals who have become multi-national outside India. Their, known business is a steel factory or any other industry like this. But actually the paper industry is & bifferer industry for them, through which they are trying to suck the blood of the nation. This is their actual industry. It is high / time that the press should be rescued from their dirty hands. By that I do not mean that the Government—whether this Government or the Government to come should pressurise the press and control it by censoring it It —should actually be autonomous. And the best way to practise au-practise autonomy for the press is that every recognised political party should be given assistance and aid to have its own press to place its viewpoint before the people. Particularly the Minister may help the nation by seeing that whatever we are speaking here, at least a gist of it in the form of synopsis, may be published as Parliamentary Bulletin in all the languages—Hindi, English, and other non-Hindi regional languages so that the nation may know what happens in Parliament. In fact, when Parliament meets, it is practically the epi-centre and whatever happens here should be known to the entire nation. This is my suggestion which the hon. Minister may examine.

None of these papers is serving any national purpose, nor any rational purpose. Here and there, occasionally a journalist brings out something on corruption or some such thing.—I do not want to name the journalist or the newspaper which recently made a signal contribution to our body politics. That way it happens only once in a blue moon but never all throughout

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): Mr. Mallick, please finish now. I am calling the Minister at 4.15.

SHRI HAREKRUSHNA MALLICK: This will be self-complementary to the people who are trained in press affairs, that is, those peonle who want to be journalists, writers and all that. They

[Shri Harekrushna Mallick]

can get very good incentive if the Government comes to their help by giving them loans for setting up presses and all that so that a team of talent could serve the nation to the best of its ability because today we are living in an era of publicity and publicity must be given proper scope so that everybody is able to contribute.

With these few words, Sir, I urge upon the hon. Minister to come forward with a suitable legislation to see that this aspect is given proper shape. Thank you.

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI VASANT SATHE): Sir, I thank Mr. Jha for bringing this idea before the House in the form of this Bill. If I have understood him correctly, Shiva Chandraji's intention, probably, was genuine and sincere inasmuch as he wants the press, which according to him is in the clutches of big industrial houses and business houses, to be free. He also wants poutical parties to have a greater freedom to propagate their ideas and views in the country. Therefore, he thought—and in my humble opinion, simplistically—that aU that you have to do is to bring a law and say that there should be two types of press, take over the entire big press which is in the hands of monopolists and others. Nationalise and put it in charge of the Planning Commission, under a Board, and, secondly, give five lakh rupees per political party recognised by the Government and they will have their own free press, political press. This is, in short, what the Bill suggests if I have understood it correctly. But then, as many hon. Members have expressed themselves, let us for a moment consider: will this achieve the objectives which Shiva Chandraji has in mind?

Sir, I can say at the outset that taking over of the, press or publication of newspapers will not ensure freedom of the press. And it is far from our mind. We have no idea of taking over the press at all as far as newspapers are concerned. There is a history pt press in this country of more than a hundred years. It has been mainly by the journalists—eminent men and men in public life and political life—who started the press. You might be remembering, there was a saying:

qk cffa JJHprfilsr $> tff SHsPSfR ff^Wf

Akhbar was considered even more powerful than the gun. If you wanted that, they said, "Start a newspaper". Newspapers in this country were started by eminent people. Nearly aU our great leaders have been editors in their own times, so many important Ipeople. So there is a traditipn. We believe in that tradition We believe in the freedom of the press, the freedom of expression. It seems there is a common complaint from all the Members, most of those belonging to the Opposition—those who have spoken today and spoke the other day have unanimously complained— that they do not get coverage in the press, the press is not on their side. Rameshwar Singhji was saying just now that even imortant events are not covered and whatever important things he speaks are not reported in the press. Now, he was blaming the Government for it. But, Sir, I find that Rameshwar Singhji and other Members of the Opposition, including the Mover of this Bill, Shri Shiva Chandra Jha ji, get more coverage in Sansad Sameeksha. I hear it every day on radio and television and I find that they get more coverage on radio and Doordarshan than what they get in the press; particularly in the so-called national press, there is hardly ever a mention. But every day they find a mention over the radio and TV, even if it is one sentence pf

importance on what they have said. It is, therefore...

SHRI SANKAR PRASAD MITRA (West Bengal): Sometimes the names are wrong.

SHRI VASANT SATHE: Sometimes the names may be mistaken. It is human failure. Sometimes a slip is possible. But effort is made to give projection. You can blame what is happening in the pi-ess. It is a free press. That *i** the test of freedom. They are equally blamed. I would say that in fact that is the test. The press goes on being unfair both to the Opposition and the ruling party. Then, to whom are they fair?

SHRI GHULAM RASOOL MATTO (Jammu and Kashmir): They are fair to all.

SHRI VASANT SATHE: They are either fair to all or they are fair to none, but in that they are equal. The truth is that in our country also the press is answerable mainly to the employers, the owners of the press. It is their policy which they pursue. *(Inter-fuptions)* The employers also, besides the political party. If it serves their purpose, they will be On their side; if it does not serve their purpose, they will not be on their side. Therefore, if you really want real freedom, the answer is not nationalisation, the answer is not to give five Iakhs of Srupees, because I will tell you honestly that you cannot run a paper in five lakhs of rupees in this country today; even fifty Iakhs of rupees will not be sufficient. Therefore, that is not the answer The answer could be a co-op«?rative effort by the journalists themselves because on their own they cannot find the money, but collectively they can think of something. This is in keeping with the spirit of socialism in which you believe, I believe, we all believe. So if some such thing could be thought of, well, one could sympathetically consider. But this is not what you have placed in this Bill. As far as thia Bill is concerned, I understand the spirit in which Shiva Chandra Jha ji has brought it and other Members have spoken about it I entirely agree that it will be dangerous, whichever party may be in power today—and nobody can ever say that only a particular party will be in power for all times. The Opposition had been in power. They got a golden opportunity in 1977. Unfortunately, they could not hold it for long. It is not our fault. Well, they can always get a chance. Therefore, whenever you bring a law, you must never think in terms only of what is today. I am not interested. People were saying, "You were giving it to Mr. Vasant Sathe". I am telling myself that that I do not want this. I do not want to have the Press in the hands of the Government at all. I am quite happy where they are. Let them be free, free to do whatever they like, entirely. Therefore, as far as Press is concerned, our view is that.

As far as the monopoly control is concerned, we already now have received the report of the Press Commission. That is under consideration. What should be done on the various recommendations such as delinking of the Press from the monopoly houses, that will be examined. We will give thought to it, and whatever helo we can pive to encourage the small and medium language newspapers which are run mainly by the journalists, journalist-editors, that we will try to do. To that extent, we think there will be greater freedom of the Press if the journalists themselves are encouraged.

Therefore. Sir, I think, in the light of this, I would request Shiva Chandra Ji. Your objective

[Shri Vasant Sathe]

is laudable. But the method by which you want to serve it, instead of achieving the objective, has the danger of defeating the objective itself. Therefore, I would request, through you, Sir, Shri Shiva Chandra Jha, to withdraw this Bill. Now that he has expressed the wish and has brought it to the notice of the House and that many hon. Members have also given their views, I think he will respect the views of the House.

Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ARVIND GANESH KULKARNI): Mr. Shiva Chandra Jha.

[Mr. Deputy-Chairman in the Chair!

श्री शिव चन्द्र झा : उपसभापति महोदय, मैं तमाम सदस्यों को जिन्होंने इसमें भाग लिया, मेरे विधेयक पर बोलने में भाग लिया और बैठ करके विचारों के आदान प्रदान के समय उपस्थित थे, उन सबों को धन्यवाद देता हूं । मंत्री महोदय ने भी कोशिश की मेरे विधेयक को समझने की कि यह स्प्रिट है । लेकिन दुर्भाग्य यह है कि शायद जब मैं बोल रहा था पिछली दफा तो ये मौजूद नहीं थे पूरे समय तक । कुछ समय तक थे उसके बाद चले गये किसी को देकर जिम्मेदारी कि अब तुम देख लेना इसको । वजह यही है कि तमाम बातें इनके सामने नहीं आ सकीं ।

श्री उपसभापति : आपकी स्पीच पढ़ी होगी ।

श्री शिव चन्द्र झा : वह बात अलग है। आप तो जानते ही हैं कि संविधान के छोटे से छोटे आर्टिकल का कितना इन्टरप्रेटेशन होता है, जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मतलब निकालते हैं तब बात बैठती है । तो बहुत छोटा होता है विधेयक, वह मोटा रूप देता है, बर्डस आई व्यू जिसको कहते हैं, वह रखता है । लेकिन उसका क्या मतलब है यह जब मैं बता रहा था तो उस वक्त ये नहीं थे और इसीलिए शायद ये उन्होंने कहा कि मेरी भावना ठीक है, स्प्रिट ठीक है, आब्जेक्टिव्स ठीक हैं लेकिन मेरे साधन जरा सा ठीक नहीं हैं, रास्ता ठीक नहीं है । लेकिन मंत्री महोदय ने जुबान को रोकते रोकते या अपने को कन्ट्रोल करते करते कहा कि हां कुछ इंडियन प्रेस के साथ गड़बड़ है । वह ओनरशिप को एकाउंटेबुल है, जिनका प्रेस है । लेकिन वह हमारा एकाऊंटेबुल नहीं है, मालिकों का एकाउंटेबुल और प्रेस कमीशन ने जो डी-लिंकिंग की बात रखी है, उसमें सोच भी है और उन्होंने कहा कि यदि कोआपरेटिव वाले यह बात रखते, तो कुछ सोचा जाता । तो स्पष्ट है कि यह भी असंतुष्ट हैं ।

प्रेस का जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, अभी वह संतोषजनक नहीं है । उसमें स्वतंत्रता का जो जेनविन रूप होना चाहिए वह नहीं है । कुछ करना चाहिए । प्रेस कमीशन ने कुछ करने के लिए सिफारिशें की हैं । अब यह अपने मन में भी है कि ऐसा होता कोआपरेटिव का, तो कुछ होता । तो साफ है कि भारतीय प्रेस की अभी जो बनावट है, वह जो आदर्श है प्रेस की स्वतंत्रता का, उसके अनुकूल यह महसूस करते हैं कि दाल में जरूर काला है । फीडम आफ दी प्रेस उस रूप में है जिस रूप में और जगह है, लेकिन उस हकीकत में वह फीडम नहीं है जो होनी चाहिए । यह भी महसूस करते हैं। लेकिन अफसोस है कि जब मैं विचारों का आदान-प्रदान रख रहा था, तब यह यहां नहीं थे । मैं तो कहता हूं कि जनतंत्र आप मजबूत करना चाहते हैं, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं ? आप यह भी कहते हैं, मान लेते हैं कि दिल से आप कहते हैं कि आप समाजवाद लाना चाहते हैं, हकीकत में जनतंत्र में क्या होता है ? जनतंत्र में क्या चाहिए ?

जनतंत्र में चाहिए कि हम आपको खूब क्रिटिसाइज करें, आप हमको रोके नहीं,

मोटे तौर पर मैं आपकी खूब निंदा करूं और आप सुनते रहें, आप हमारी निंदा करें, मैं सुनता रहूं। तो टालरेंस ही उसका आधार होता है। मुझे बड़ी हैरानी हुई जबकि सुकुल जी बहुत गंभीरता से हमारे समाज के, श्रीमन्, ट्रेडिशन कहिए या कस्टम कहिए कि बात को साफ न भी कर सकें, तो कुछ गंभीर रूप दे दें, मुद्रा तो हो जाए कि बहुत अच्छा विचार आ रहा है। श्रीमन्, सुकुल जी ने कहा कि मैं तर्क ही नहीं समझ सका कि सरकार पैसा देगी, पोलिटिकल पार्टी को, तो मैं कहूंगा कि यह तो हम सभी यहां देखते हैं कि विरोधी एम पी को भी रु 51 मिलता है और इनको भी रु 51 मिलते हैं, सरकार से मिलते हैं। लेकिन बात समझिये, उसी सरकारी खजाने से रु 51 उनको भी आती हैं और हमें भी। लेकिन हम क्या करते हैं, दिन-रात उनकी मुखाल्फत करते है आलोचना करते है, विरोध करते हैं, या हल्ला करते है।

बर्दाश्त क्यों किया जाता है? इसके दर्शन पर गौर करें, बात यहीं पर आती है, हमें बहुत अफसोस है कि पार्टी के कुछ हमारे साथियों ने भी कह दिया कि हम तो साठे साहब का साथ मजबूत कर रहे हैं। हम तो साठे साहब के बाद में जो साठे साहब आयेंगे, उनका भी हाथ मैं तोडना चाहता हूं, चाहे हमारे ही लोग क्यों न आयें।

मैं इस दर्शन पर जोर देना चाहता हूं कि क्या हमारी बनावट में एक और हम विरोधी एम० पी० को भी रू० 51 दें, वही सुविधाएं दें, भत्ता वही दें और रूलिंग पार्टी के एम० पी० को भी वही सुविधायें दें, क्यों ? हम क्या करते है हम यहां आकर के दिन-रात, सुबह से शाम तक इनकी आलोचना करते हैं, क्यों दिया जाता है ? इसके पीछे क्या दर्शन है, हमको बताएं। हमारे देश में तो दर्शन के लिए हम हैं ही दुनिया में नामी। यह इसलिए है कि हम जनतंत्र चाहते हैं, हमारे समाज में जनतंत्र हो, सरकारी पैसा हमको आता है, सरकारी पैसा आपको भी जाता है। हम आपका विरोध करते हैं निन्दा करते हैं, आलोचना करते हैं ताकि यह जनतंत्र का फूल फले, खिले, सुगंधित हो। गुलाब तब तक नहीं होगा जब तक कि कांटे नहीं हों। कांटे के साथ आपको गुलाब मानना पडेगा। तो विरोधी को बोलना, विरोधी का होना जनतंत्र में एकदम बेसिक है। यही तो दर्शन है। इस बात को हमारे मंत्री महोदय नहीं समझ रहे हैं, क्यों ? हम को सरकार से पैसे दिए जाते हैं। क्यों नहीं एक विधेयक लाकर कहें कि ये लोग हल्ला करते हैं इनको पैसे नहीं देंगे ? लेकिन आप यह कर नहीं सकते क्योंकि संविधान की अडचन है और संविधान के पीछे भी नेताओं का वह दर्शन है कि हम विरोध पक्ष को रखेंगे, वही सुविधा देंगे, वही भत्ता देंगे, वही पैसा देंगे। विरोध पक्ष की सुविधा हो, वह मजबूत हो, यह दर्शन है। अब इसी दर्शन पर आधारित मेरा विधेयक है। मैंने कहा जनता को कोई छूता नहीं "लोक लहर" को कोई छूता नहीं "न्यू एज" को कोई छूता नहीं। इसका मतलब क्या होता है। लिटरल मिनिंग में नहीं जाना है, लाइब्रेरी में भी जाकर हम लोग छूते हीं हैं। दस-पन्द्रह-पचास ग्राहक उसके भी रहते हैं। छूने का मतलब यह नहीं कि ज्यादा से ज्यादा लोग नहीं पढ़ते हैं। पढ़ नहीं पाते क्योंकि फाईनेन्शली मजबूत नहीं है, उनका प्रेस इतना बडा नहीं है, उनके पास इतना कागज नहीं है, उनके पास स्टाफ नहीं है, रिपोर्टस नहीं है इतने कि वे रख सकें और दूसरे प्राइवेट प्रेस का मुकबला वह कर सकें। इसलिये वह कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। यह दिक्कत है। छूने का मतलब यह नहीं है कि उसमें अच्छे विचार नहीं हैं। मैं हर हफ्ते उनको पढता हूं, दूसरे अखबार मंगा कर पढ़ता हूं। छूने का मतलब है, जनता

[श्री शिव चन्द्र झा]

में ज्यादा पैमाने पर नहीं जाता। इसलिये बुनियादी बात यह है कि पैसे के मामले में वहां लोग कमजोर हैं।

अब आप आइये "जन शक्ति" पटना। वह भी सी पी आई का अखबार है जो टिक-धन टिक-धुन कहते है जैसे हम लोगों का पटना में निकलता है, टिक-धुन चलता है जो सप्ताह भर चलता है फिर बंद हो जाता है। लेकिन फाइनेंशली अब कुछ मजबूत हो रहे हैं, प्रेस बैरन्स से पैसा आता है। फाईनेंशियली मजबूत है "जन शक्ति" जिसको बिहार के लोग पढ़ते हैं क्योंकि जो प्रेस चलाने का तरीका है उसमें सक्षम है, उनके अखबार लोग पढ़ते हैं। यह मेरा मतलब है। तो मैं चाहता हूं, उनको आप मजबूत करेंगें। मैंने 5 लाख जो बताया वह सिम्बोलिक है, आप करोड़ दे दीजिये। आपने कहा 5 लाख में क्या अखबार चलेगा, मैं मानता हूं। तो एक करोड़ दे दीजिए। छः-सात-आठ रिकान्नाइजड पार्टियां हैं, आठ करोड़ रु० साल में लगेंगे तब उनका अखबार मजबूत होगा। ये अपने दृष्टिकोण से आपकी दिन-रात आलोचना करें, अपनी विचारधारा से आपकी नुक्ताचीनी करे। वह हर तरह से प्रहार करें जो जनतंत्र में आप चाहते हैं। यह जो होगा यह आलोचना का आस्पेक्ट होगा उसी प्रकार का जिस के लिये हम विरोधी पक्ष वालो को आप डी ए और टी ए देते हैं, सब सुविधायें देते हैं। सुबह से शाम तक हम आपको मुर्दाबाद करते हैं और आप प्रोटेस्ट करते हैं। वैसे ही अखबार वाला भी, पैसा मिलेगा, तो मजबूत होगा और गरज कर बोलेगा। इस से लोकतंत्र में आलोचना का स्तर ऊंचा होगा। और यह प्राइवेट प्रेस है जिसके डी-लिंकिंग की बात आप दिल में सोचते हैं कि होना चाहिए। यह बात जरूर है कि ये मालिक लोग हैं और आप कई बार बोल चुके हैं—दे आर इन्स्ट्रूमैन्ट स आफ व्हेस्टेड इंटरेस्ट एण्ड एजेन्टंस आफ फारेन व्हेस्टेड इंटरेस्टस—न जाने क्या क्या आप बोलते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं यह फैसला आप से नहीं होगा। यह फैसला लीडर से होगा। यह फैसला ऐसा नहीं कि मिनिस्टर से होता है। जब तक लीडर, फसला नहीं करता और लीडर जब फैसला कर लेंगे तो कल आप ही कहेंगे ठीक कदम है। उपसभापति महोदय बैंक राष्ट्रीयकरण का दिन मुझे याद है। फोर्थ लोकसभा में मैं था। राष्ट्रीयकरण के दो दिन पहले राष्ट्रीयकरण-राष्ट्रीयकरण, क्या उससे होने वाला है ऐसा कहते थे। जहां आदेश जारी हुआ सब ढोल बजने लगे। बहुत अच्छा समाजवाद है। हम समाजवाद ला रहे है। उसमें सोशलिस्ट, कम्यूनिस्ट कितने ही लोग रोज हल्ला करते थे लेकिन प्रधान मंत्री रोज उनको कहती थी, उस समय स्वतंत्र पार्टी भी थी, समस्या ऐसे ही हल करना चाहते हैं। लेकिन जब प्रेसिडेंशल आर्डिनेंस जारी हुआ तो सबों के दिमाग खुल गये कि सचमुच यह विकास का कदम है। तो मंत्री महोदय भी इसको पकड़ लें। जब फैसला होगा तो सभी कहेंगे कि असल विकास का काम अब हो रहा है। मैंने कहा कि राष्ट्रीयकरण और मेरे एक बुजुर्ग साथी ने कहा राष्ट्रीयकरण नहीं, समाजीकरण। एक सैद्धांतिक रूप में यह बात आती है। लेकिन मैं बात को रखना चाहता हूं। चीनी मिलें है, आपके इलाके में या मेरे इलाके में, उसका समाजीकरण आप कैसे करेंगे? आपने समाजीकरण की बात कही लेकिन समाजीकरण तो राष्ट्रीयकरण के बाद ही होगा। पहले आप डिब्बे में घुसियेगा तब खोजियेगा कि आपकी सीट कहां है, कैसे हमको कहां पर बैठना है। तो समाजीकरण करने के लिये पहले आपको डिब्बे के अन्दर घुसना होगा। यह स्टेट की जनरल बिल है बावजूद खराबियों के,

लोगों की, जनता की बिल है समाजीकरण की, उसके मार्फत समाजवाद आयेगा। खराबियां उसमें होंगी, उसको सुधारेंगे लेकिन आप बतावें कि चीनी मिलों का हम समाजीकरण तुरन्त कैसे करने लग जायेंगे। पहले स्टेट उसको टेक-ओवर करे, फिर मजदूरों का उसमें पार्टिसिपेशन होगा, पंचायत होगी तब जाकर ही तो समाजीकरण होगा। तो ये सब सुपरफोशियल बातें हैं यह समाजीकरण नहीं है। इसके लिये पहले डिब्बे में घुसना होगा, राष्ट्रीयकरण करना होगा।

श्रीमन, यहां पर कहा गया कि बड़ी प्रेस जो एक लाख से ऊपर की होगी, ये 32 है या 33 है। प्रेस कमीशन ने कहा कि 1 लाख। आप कहिये कि 10 हजार वालों को नहीं लेंगे, 1 लाख से ऊपर सर्कुलेशन जिसकी हो उसको लेंगे। छोड़िये एक लाख से नीचे रहने वालों को और 1 लाख से ऊपर वालों को जो 33 अखबार है उनको ही आप ले लीजिये। अब कहा जाता है कि प्लानिंग कमीशन में वह क्षमता नहीं है। क्या आपने भी विश्वास खो दिया है। सरकार का मतलब है आप लोग। क्या आप मानते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स वहां है, टेक्नोक्रेट्स वहां है, भ्रष्टाचारिये ये सब वहां है, लेकिन ये सब माइनर चीजें है। ओवर-आल देश के लिये, फिजिकल पार्टिसिपेशन में ये माइनर चीजें हैं। हमारे देश में नेशनलाइज्ड मैडिसन है। जिला हैडक्वार्टर पर भी थानों में भी 24 घंटे कंपाउंडर रहेगा। एक साधारण गरीब के लिये भी फाटक खुला हुआ है कि वह मरीज को रात में भी ले जा सकता है। लेकिन चाहे वहां दवा न हो, कंपाउंडर न हों। इसका क्या मतलब होता है। दवा नहीं है, मैडिसन नहीं है, यह गलत है। लेकिन सवाल यह नहीं आता है कि क्यों नही है, मगर साधारण देहात के लोगों के लिये तो फाटक तो कम से कम उसके लिये खुल गया। यहीं देखिये, दिल्ली में आल इंडिया मैडिकल इस्टीट्यूट है। जो मुझ को मालूम हुआ, जो मैं देख रहा हूं, वह राजनारायण ही था हेल्थ मिनिस्टर कि जिस ने फाटक खोल दिया आल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का कि वहां साधारण से साधारण आदमी जायगा और सब का बाकायदा इलाज वहां होगा मैं तो वहां जाता नहीं लेकिन मेरे इलाके के लोग आते है और कहते है कि वहां बहुत अच्छा तरीका है। उस में सिफारिश की कोई जरूरत नहीं है और सब के लिये लाइन लगी हुई है और सब का इलाज होता है और जो रिपोर्टें मेरे पास आयी है उन से पता लगता है कि जिन का कोई परिचय नहीं है उन सब का काम भी वहां हुआ है। आधा घंटा, एक घंटा लगा है, लेकिन कायदे से इलाज हुआ है। मान लीजिये कि कोई डाक्टर खराब है या बदमाश है तो दूसरी बात है, लेकिन राजनारायण ने उस का फाटक खोल दिया है सारी जनता के लिये। पहले ऐसी बात नहीं थी तो राष्ट्रीयकरण का मतलब है कि साधारण जनता के लिये आप डिब्बा खुला रखें। उस को क्वालिटेटिवली अच्छा कीजिये। उस का सोशलाइजेशन करिये, लेकिन उस से भागना उचित नहीं है। तो मैं समझता हूं कि यह जो आउट लुक आप ले लेते है तो ऐसा कर के आप विरोध पक्ष का ही विरोध नहीं कर रहे हैं बल्कि आप तो अपने बीस सूत्री कार्यक्रम का भी विरोध कर रहे है। प्रधान मंत्री के कार्यक्रम का भी विरोध कर रहे हैं उन के कार्यक्रम में जो थोड़ी बहुत अच्छा है उस का भी आप विरोध कर रहे है आप को तो कहना चाहिये कि हम लेंगे मैं आप को दूसरा उदाहरण देता हूं हमारे नेता थे डाक्टर लोहिया। व जमाना था 1950 का और उस सम दिल्ली मार्च हुला। वह सब यहां आ और उन्होंने अपना 14 प्वाइंट का प्रोग्र

[श्री शिव चन्द्र झा]

ला कर पं० नेहरू को दिया। डाक्टर साहब साथ गये थे। तो तमाम दर्शन को समझने वाले पं० नेहरू ने उस 14 प्वाइंट प्रोग्राम को देखा और उस के बाद कहा कि आपकी सारी बात मंजूर, तुम्हारे 14 प्वाइंट हम को मंजूर है लेकिन हमारा एक प्वाइंट है। एक प्वाइंट का प्रोग्राम है। उन्होंने पूछा कि वह क्या ? तो पंडित जी ने कहा कि इस को थोड़ा पोस्टपोन रखो। यह सब प्वाइंट तुम्हारे अच्छे है लेकिन अभी कुछ साल के लिये इन को पोस्टपोन रखो। डाक्टर साहब ने कहा कि यह क्या। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे 14 प्वाइंट सारे के सारे मान लेते है, लेकिन हमारा एक प्वाइंट का प्रस्ताव है कि इस को कुछ साल के लिये पोस्टपोन रखो। अब यह दृष्टिकोण कोई रखे तो क्या कुछ हो सकेगा। आप क्या ठहर जायेंगे राष्ट्रीयकरण करने से और अगर ठहर जायेंगे तो क्या चला सकेंगे अपने पब्लिक सेक्टर को। आप कहेंगे कि हम लेंगे तो उस में बहुत सी गड़बड़ियां है। अगर है तो उन को आप को सुधारना चाहिये : सोशलाइजेशन होगा तो जनता की सर्विस होगी। लेकिन राष्ट्रीयकरेण के नाम पर आप तो इस तरीके से भड़क जाते है जैसे 19 वीं सदी में जब स्टेट इंटरवेंशन की बात कही जाती थी इकोनामिक फील्ड में या प्राइवेट इंटरप्राइजेज में तो उस समय जानस्टुवर्ड मिल कोई रेवोल्यूशनरी नहीं था, कार्ल मार्क्स या ऐंजिल्स या उस के पहले राबर्ड ओवेन थे, जान स्टेवर्ड मिल तो बहुत बाद में हुआ था वह लिबरल था और स्टेट ओनरशिप और स्टेट कंट्रोल के बारे में कह देता था कि होना चाहिये क्योंकि बहुत ज्यादा अनइंप्यायमेंट है, गरीबी है तो उस की बात का विरोध होता था इसलिये कि उस से सारा स्ट्रक्चर खत्म हो जायेगा। किताबों पर किताबें भरी हुई हैं इस बात पर कि स्टेट इंटरवेंशन इकोनामी में कैसे चलेगा। जो कुछ एडम्स स्मिथ लिख कर छोड़ गया था उसी पर गाड़ी चल रही थी लेकिन जब कभी कोई कहता था कि स्टेट इंटरवेंशन होना चाहिये तो कहा जाता था कि हमारी फ्रीडम चौपट हो जायेगी। बहुत से लोग कहते थे कि हमारी सारी फ्रीडम चौपट हो जायगी लेकिन जब ऐटली के हाथ में सरकार आयी, लेबर सरकार, तो वह कोई बम फेंकने वाला नहीं था वह टेरोरिस्ट नही था। व बुद्धिमान लोग थे। पार्लियामेंटरी लोग थे, कंस्टीट्यूशनल लोग थे। लेकिन एटली ने नेशनल कार्यक्रम शुरू किया। बैंक आफ इंगलैंड, कोल, माइन्स स्टील को नेशनलाइजेशन के बिल आए। जब स्टील के नेशनलाइजेशन का बिल आया पार्लियामेंट में तो विंसटन चर्चिल बैंच पर बैठे हुए थे। उन्होंने उस वक्त कहा कि It is not a will चर्चिल क्या थे वह गांधी ही थे। उन्होंने कहा था "This is not a Bill. This is a plot by the Kremlin".

ये सब के सब लेबर वाले एटली के एजेंट है। यह बिल नहीं है यह प्लाट है। उन्होंने अपने नोजवानों को कहा था हल्ला करो। जब हल्ला किया गया तो पायलेट बिल आया। इसे हाउस आफ लार्ड में रखा गया। उन्होंने सोचा कि इसको कोई नहीं रोकेगा, इस पर कोई चर्चा नहीं होगी यह पास हो जायेगा। एकदम क्लीयर हो गया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, कोल का हुआ। लंदन में जाकर देखिये कि जो बीमार पड़ते है उनके लिये वहां क्या सुविधाएँ है। हिन्दुस्तानियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा है। वहां बड़ी फसेलीटीज हैं। हमने रेडियो खरीद लिया। सारी सुविधाएं हैं मेरा कहना है कि राष्ट्रीकरण करो। उन्होंने राष्ट्रीयकरण किया प्रशस्त मार्ग खुल गया। लेकिन आप राष्ट्रीयकरण के नाम से भड़कते हैं। आप क्या 20 सूत्री

कार्यक्रम को चला पायेंगे साठे साहब ? आप प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में थे । 57 में पूना में कान्फ्रेंस हुई थी। उस समय गौरे साहब सेक्रेटरी थे और अशोक मेहता साहब उसके चेयरमैन थे। आप भी थे न वहां पर? मैं भी था और मैं वहां पर अंग्रेजी में बोला।

श्री उपसभापति : आप अंग्रेजी में क्यों बोले ।

श्री शिव चन्द्र झा : आप कहिये कि हम करेंगे ।

श्री उपसभापति : समय समाप्त हो रहा है ।

श्री शिव चन्द्र झा : यह ठीक है कि ब्यूरोक्रेट्स के कब्जे में आ जाता है। इससे हालत खराब ही होती है। मैंने आपको बताया था कि 10 हजार से ऊपर क आप ले लें। आप 10 हजार तक नहीं लेते है तो एक लाख के अबाव जिनका सरकुलेशन है उनको ले लीजिए । दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि आप किसी अखबार को उठा कर देख लीजिए। हिन्दुस्तान टाइम्स हो या दूसरा कोई अखबार हो उसमें 3/4 अडवर्टोजमेंट होते हैं। न्यूज 1/4 होती है और विरोधी पक्ष की बातें तो न के बराबर होती हैं। मैंने एक लेख भी लिखा था आपके ऊपर. . . .

श्री उपसभापति : मेरे ऊपर ? बड़ी कृपा की आपने ।

श्री शिव चन्द्र झा : आप पर नहीं लिखा मैंने लिखा था पार्लियामेंट एंड दी प्रेजाइडिंग आफिसर। प्रेजाइडिंग आफिसर और पार्लियामेंट का क्या रोल होना चाहिये, इस पर लेख लिखा था। आप इसका मतलब अपने ऊपर ले लेते हैं तो ठीक है । दोनों का रोल किस तरह का होना चाहिए इस पर एक लेख लिखा था लेकिन अखबार ने आज तक नहीं छापा ।

श्री उपसभापति : आप मेरे पास भेज दीजिए मैं पढ़ लूंगा ।

श्री शिव चन्द्र झा : दो महीने हो गये अभी तक अखबार वालों ने नहीं छापा क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट है ।

श्री उपसभापति : आप मेरे पास भेज दीजिए ।

श्री शिव चन्द्र झा : जो लेख इनके खिलाफ हो वह यह छापेंगे नहीं । यह सब अखबार अडवर्टीजमेंट से भरा रहता है लेकिन लेख जो खिलाफ हो उसको नहीं छापेंगे ।

श्री सैयद सिब्ते रजी (उत्तर प्रदेश): यह किस भाषा में है ?

श्री शिव चन्द्र झा : अंग्रेजी में है ।

श्री सैय्यद सिब्ते रजी : इसी लिए नहीं छापा होगा ।

श्री शिव चन्द्र झा : मैं लिखता अंग्रेजी में हूं, बोलता हिन्दी में हूं और लड़ता हूं मैथिली के लिए ।

श्री वसन्त साठे : आप समझते कि भाषा को हैं ?

श्री शिव चन्द्र झा : इसलिए मैंने राष्ट्रीयकरण की बात कही है ।

श्री उपसभापति : अब आप समाप्त कीजिए :

श्री शिव चन्द्र झा : चाहे कांग्रेस पार्टी का शासन हो या जनता पार्टी का शासन हो, अगर राष्ट्रीयकरण होता है तो वह सब के लिए अच्छा होगा । यह ठीक है कि शासन में कुछ खराबिया होती हैं। कुछ आफिसर होते हैं, आई० ए० एस० आफिसर हों या कोई अन्य हो । कुछ खराबियां तो रहती हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि राष्ट्रीयकरण न किया जाय । जिस प्रकार से आई०

[श्री शिव चन्द्र झा]

ए० एस० है उसी तरह से एक आई० जे० एस० सर्विस होनी चाहिये। इंडियन जरनेलिस्ट सर्विस का एडीटर रहेगा तो, वह सब के लिए होगा। 'लन्दन टाइम्स' कोई सरकारी अखबार नहीं है, लेकिन वह प्रो-सरकार है। चाहे एटली की सरकार हो या चर्चिल की सरकार हो, वह ब्रिटिश सरकार के साथ रहता है। लेकिन उसकी एक न्यूट्रैलिटी रहती है, आब्जेक्टिविटी रहती है। मैंने एक लाख के सरकूलेशन की बात कही है। धावे जी ने भी उसका उल्लेख किया है। जो छोटे पेपर होंगे वे तो प्राइवेट लोगों के पास रहेंगे ही। उनको कंट्रोल करने की बात मैंने नहीं कही है। जिनका एक लाख से ऊपर का सरकूलेशन है उनकी बात मैंने कही है। **दो** तरह के अखबार सदा से किसी भी देश में रहे हैं।

श्री उपसभापति : अब आपका दर्शन स्पष्ट हो गया है। आप अब समाप्त कीजिए।

श्री शिव चन्द्र झा : मैं समाप्त कर रहा हूं। अन्त में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि यहां की लायब्रेरी में एक किताब है, 'कांसेप्ट आफ प्लान्ड फ्री प्रेस'। इसके लेखक हैं श्री शिव चन्द्र झा, मूवर आफ दिस बिल। यह किताब यहां की लायब्रेरी में है। इसको आप ठीक से पढ़िये। उसके बाद हम लोग बात करेंगे। एक लाख की जो बात कही गई है उसको अगर आप मान लेंगे तो उससे कोई गड़बड़ी नहीं होगी। आपने कहा कि हमारे देश में एक ट्रेडीशन रही है। मैं जानता हूं कि हमारे देश में मराठी का 'केसरी' अखबार था जिसको तिलक ने निकाला। इसी तरह से 'इंग इंडिया' और हरिजन अखबार गांधी जी ने निकाले थे। हर मुल्क में शुरुआत में छोटे छोटे अखबारों का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा। जौन पीटर ने अमेरिका में अमेरिकन फ्रीडम के लिए काम किया और उसके कारण बाद में अमेरिका अंग्रेजी की गुलामी से दूर हुआ। समाचार-पत्र एक बहुत बड़ा हथियार है। इनसे बहुत बड़ी बड़ी चीजें हासिल की जा सकती हैं। दूसरे देशों, रूस आदि की बात मैं नहीं करना चाहता हूं क्योंकि हिन्दुस्तान में जो सिस्टम है, जो यहां की बनावट है वह अमेरिका और इंगलैंड से मिलती-जुलती है, इसलिए मैं उनका उदाहरण दे रहा हूं। 5 P. M. प्रोफिट मेकिंग बनावट है, इस हिसाब से मैंने कहा। इसलिए आप इसको कबूल कर लें या यह कहें कि मैं इस पर विचार करूंगा, हम और बात करेंगे। आपको घबड़ाने की जरूरत नहीं है। यह दृष्टिकोण जो है इससे आप डरिये नहीं। गांधी जी ने कहा है कि निडर होकर अपने विचारों को रखें। आप डरिये नहीं। इसलिए आप . . .

श्री उपसभापति : क्या आप इसको वापस ले रहे हैं।

श्री शिव चन्द्र झा : नहीं।

MR, DEPUTY CHAIRMAN; The question is:

"That the Bill to provide for the planning and the freedom of the Press, b$_e$ taken into consideration".

The *motion was negatived.*

MESSAGES FROM THE LOK SABHA

(I) The Air Corporations (Amendment) Bill, 1982.

(n) Th$_e$ Prevention of Cruelty to Animals (Amendment) Bill, 1982.